संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज | समूह संपादक : रवि भारद्वाज | देहरादून, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 ₹ 1 | www.actionindialive.com | Facebook.com/actionindialivee

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्षः 17 अंकः 107 पृष्ठः 08 | RNI : UTTHIN/2009/31653

actionindiaddn@gmail.com | उत्तराखण्ड संस्करण | दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़

RKB GROUP Rakesh Bhardwaj Group

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की।

परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, ये मेरी गारंटी-मेरा वादाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किया गया। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ संसद में सीटों की संख्या को भी बढाया जाना है। पीएम मोदी इस दौरान सदन में बोलते हुए सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

'अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा'

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी एक्टिविस्ट, संविधान के जानकारों से बात हुई। यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं एक साथ निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी।

पीएम मोदी ने सभी दलों को भरोसा देते हुए कहा, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूं। वादा की बात करें तो वादा करता हूं। जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। 'हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं'

मोदी का वादा

- परिसीमन पर दक्षिण भारत के हर राज्य का दूर किया भ्रम, कहा- किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... जी नहीं! उसका हक है। हमने कई दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है। मोदी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ है और हमें शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हो... ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही, जिनके काल में जो परिसीमन हुआ, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं... क्योंकि अगर नीयत साफ है, तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।

विपक्ष के सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने के आरोपों का प्रधानमंत्री ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। हम महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं। 2023 में इसी सदन ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को स्वीकार किया था। अब हमें तकनीकी बहाने बनाकर इसे रोकना नहीं चाहिए।

महिलाएं पंचायत से पार्लियामेंट आना चाहती हैंः प्रधानमंत्री मोदी

- आरक्षण को महिलाओं का हक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इसे लटकाए रखने के पाप से मुक्ति पाने का अवसर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से सरकार की ओर से लाए गए तीन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया

चर्चा

- देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान है और इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए: पीएम मोदी

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में सभी दलों से सरकार की ओर से लाए गए तीन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया ताकि इससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण को रोका जाता रहा है। अब इसका प्रायश्चित करने का समय है। वे मानते हैं कि देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान है और इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े तीन विधायकों पर एक साथ जारी चर्चा में भाग लिया। चर्चा कल तक चलेगी और अंत में गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। विधेयकों में एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। चर्चा में भाग लेते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री ने विधेयकों को राजनीतिक बताने के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया तो दूसरी ओर स्पष्टीकरण भी दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। साथ ही लोकसभा की सीटों में इजाफा समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से विधायिका का सामर्थ्य बढ़ेगा। इसे राजनीति के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। उन्होंने कहा, ह्लहम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... जी नहीं! उसका हक है। हमने कई दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है। मोदी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ है और हमें शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हो... ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही, जिनके काल में जो परिसीमन हुआ, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं... क्योंकि अगर नीयत साफ है, तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।

'समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें'

पीएम ने कहा कि 2023 में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तब लोग कह रहे थे, जल्दी करो। 2024 में संभव नहीं हो पाया क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो पाता। अब 2029 में हमारे पास समय है, अगर 2029 में भी नहीं करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। उन्होंने कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मन:स्थिति एवं नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार करती हैं। भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को हमेशा इसका नुकसान उठाना पड़ा है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यह था कि सबने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का विधेयक पारित किया था। उन्होंने कहा, अगर हम सब साथ आ जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा।

आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें आरक्षित करना है अनिवार्य

चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को कक्षा प्रथम एवं उससे पूर्व की कक्षाओं में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी विद्यालय अपनी आरक्षित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट एवं उज्ज्वल पोर्टल पर 11 मार्च से 20 मार्च 2026 तक अपलोड करें।

लोककसभा में गुरुवार को सरकार की ओर से परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण लागू कराने से जुड़े तीनों विधेयकों को पेश किया गया। गृहमंत्री शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा आने पर शाह ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण किसी भी तरह से मंजूर नहीं है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टलाः टैक्सीइंग के दौरान दो विमान के पंख आपस में टकराए;

आपस में टकराए दो विमानों के विंग, यात्री सुरक्षित

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब टैक्सीइंग के दौरान स्पाइसजेट का एक विमान अकासा एयर के विमान से टकरा गया। इस घटना में दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री और क्रू पूरी तरह सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट का इ737-700 विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसका दाहिना विंगलेट दूसरे विमान से टकरा गया। इस टक्कर से दूसरे विमान के लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को भी नुकसान हुआ। फिलहाल तकनीकी जांच जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

अकासा एयर की फ्लाइट वापस बाय पर लौटी

16 अप्रैल 2026 को दिल्ली से हैदराबाद जा रही अकासा एयर की उड़ान दढ 1406 को तकनीकी और परिचालन कारणों से वापस पर लौटना पड़ा। शुरूआती जानकारी के अनुसार, जब अकासा एयर का विमान खड़ा था, उसी समय किसी अन्य एयरलाइन के विमान ने उससे संपर्क (टक्कर जैसी स्थिति) कर ली।

अकासा एयरलाइन की ओर से बताया गया है कि सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें समय पर विमान से उतार लिया गया। अकासा एयर ने यह भी कहा है कि उनके ग्राउंड स्टाफ यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था कर रहे हैं।

बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के तबादलों से संबंधित याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी का ट्रांसफर करने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा हर जगह होता है, पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर सहमति जताई कि निर्वाचन आयोग को इस संबंध में राज्य सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि इस बिंदु पर कानून की बात खुली रहेगी। याचिका वकील अरका कुमार नाग ने दायर की थी। इसके पहले याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

बंगालः ट्रिब्यूनल में जिनके नाम उन्हें कोर्ट ने दिया वोट का अधिकार

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से ठीक पहले तक अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले लोगों को **मतदान का अधिकार दिया जाएगा। एसआईआर डाल सकता है मुस्लिम बहुल और**

कम मार्जिन वाली सीटों पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से दो दिन पहले तक मंजूर किए जाएंगे, उन्हें आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल 2026 तक अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए।

व्यापक वार्ताः भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को मिली नई गति

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित एवं स्वच्छ तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे दायरे की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इस बैठक में रक्षा, तकनीक, व्यापार, नवाचार, कौशल विकास और काउंटर-टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में कुल 15 ठोस परिणाम सामने आए।

दोनों नेताओं ने विशेष रूप से हाई-टेक्नोलॉजी सहयोग को भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी का केंद्रीय स्तंभ माना। ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दौरे पर खास ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि आज हैदराबाद हाउस में उन्होंने आपसी रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की और साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

द्विपक्षीय

- निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे दायरे की समीक्षा की गई

देश की खुदरा महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 3.2 फीसदी के स्तर पर आई

नई दिल्ली। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.21 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि जनवरी महीने में यह 2.74 फीसदी के स्तर पर रही थी। महंगाई के यह आंकड़े आधार वर्ष 2024 वाली नई श्रृंखला पर आधारित हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों में बताया कि खुदरा महंगाई दर में यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य, पेय पदार्थ, और ईंधन की कीमतों में तेजी के कारण आई है, जो 2024 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला के तहत दर्ज की गई है।

जनगणना-2027 विकसित हरियाणा की आधारशिलाः मुख्यमंत्री सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में स्व-गणना का शुभारम्भ करते हुए। साथ में हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा। (16.04.2026)

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर कर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने प्रदेशवासियों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वीरवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल और समय की बचत करने वाली प्रणाली है। यह पहल प्रधानमंत्री के ईज ऑफ लिविंग और डिजिटल इंडिया के विजन को और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 विकसित हरियाणाझविकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राज्य के समग्र और न्यायसंगत विकास की आधारशिला है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा,

प्रक्रिया

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन कर हरियाणा में की जनगणना प्रक्रिया की शुरूआत

जिसमें मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों को डिजिटली स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सटीक और विश्वसनीय जनगणना आंकड़े ही ऐसी नीतियों और योजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र हमारी जनगणना, हमारा विकास को दोहराते हुए कहा कि यह संकल्प हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा।

भ्रांतियां दूर की *परिसीमन और सीटों में बढ़ोत्तरी के बाद दक्षिण भारत के राज्यों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत में बदलाव नहीं होगा*

परिसीमन भी पहले जैसी प्रक्रिया से होगाः अमित शाह

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि से राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनित्व प्रतिशत पहले के भांति बना रहेगा। वहीं, सरकार पिछली बार देश में हुई परिसीमन की प्रक्रिया को ही दोहराएगी। इससे जुड़ा विधेयक कांग्रेस के परिसीमन अधिनियम जैसा ही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से लाए गए तीन विधायकों से जुड़ी भ्रांतियां को दूर करने के लिए लोकसभा में आज चर्चा का संक्षिप्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह विषय पर विस्तार से अपनी बातचीत कल रखेंगे लेकिन इस मुद्दे पर वे आज कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके ठीक बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'आज रात भी इस पूरे विषय पर कोई भ्रांति ना हो इस उद्देश्य से वह संक्षिप्त रूप से अपनी बातचीत रखना चाहते हैं।' अमित शाह ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए वर्तमान सीटों में 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

543 में 50 प्रतिशत सीटें जोड़ने से आंकड़ा 816 होता है और 850 असल में राउंडअप फिगर है। वर्तमान में भी 543 पूर्ण आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि परिसीमन और सीटों में बढ़ोत्तरी के बाद दक्षिण भारत के राज्यों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत में बदलाव नहीं होगा।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होगी और उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23 हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण भारत के सभी पांच राज्यों की वर्तमान में 129 लोकसभा सीटें हैं और प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है। यह बढ़कर 195 हो जाएंगी और प्रतिनिधित्व 23.97 प्रतिशत हो जाएगा।

स्पष्ट किया

- तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होगी और उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23 हो जाएगा

लोकभवन में एक ही स्थान पर मिलेंगी सुविधाएं

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया

शिलान्यास

- परियोजना में पहाड़ी वास्तुकला को आधुनिक तकनीक के साथ समन्वित किया गया है

देहरादून/टीम एक्शन इंडिया
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। इन भवनों के निर्माण के बाद एक ही परिसर में विभिन्न विभागीय एवं जनसुविधाएं समेकित रूप से उपलब्ध होंगी।
प्रस्तावित योजना के तहत प्रथम भवन में समेकित डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। द्वितीय भवन में सूचना परिसर एवं कैफेटेरिया, तृतीय भवन में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय तथा चतुर्थ भवन में उद्यान विभाग का कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इन भवनों के निर्माण से लोक भवन परिसर में सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनेगी तथा आमजन को त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पहल समय एवं संसाधनों की बचत के साथ प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाएगी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि परियोजना में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला को आधुनिक तकनीक के साथ समन्वित किया गया है, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पहल सुशासन एवं सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में विभिन्न विभागों के कार्यालय होने से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला को अपनाने से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय कारीगरों को भी लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, विधि परामर्शी कौशल किशोर शुक्ल, उप सचिव लक्ष्मण राम आर्य, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय, अधिशासी अभियंता लोनिवि नीरज त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मदरसों में दाखिले पर उठे सवाल, वीडियो आने के बाद एसएसपी ने दिए जांच के आदेश

हलचल

- देवभूमि में मदरसों से जुड़े एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है।

देहरादून/टीम एक्शन इंडिया
देवभूमि में मदरसों से जुड़े एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है।
वीडियो सामने आने के बाद राज्य स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोगों की ओर से एक व्यक्ति को बच्चों को साथ ले जाते दिखाया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति बिहार सहित अन्य राज्यों से बच्चों को देहरादून के मदरसों में दाखिले के लिए लेकर आया है। हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वीडियो के प्रसारित होते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमा सक्रिय हो गया।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।
वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि बच्चों के आवागमन और दाखिले की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में और किन दस्तावेजों के आधार पर हुई।
साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी प्रकार की नियमों की अनदेखी या बाहरी राज्यों से बच्चों के स्थानांतरण से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

आधी रात दूधाधारी चौक पर जंगली हाथी के आने से मचा हड़कंप

हरिद्वार/टीम एक्शन इंडिया
हरिद्वार नगर के व्यस्त दुधाधारी चौक पर बुधवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी अचानक सड़क पर आ गया। इससे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत और भगदड़ जैसे हालात बन गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीती रात के समय जब चौक पर वाहनों और लोगों की आवाजाही चल रही थी, तभी एक हाथी जंगल से निकलकर सीधे मुख्य सड़क पर आ गया। हाथी को देखते ही लोग इधर-उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग डर के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में जुट गए।

आईजी विम्मी सचदेवा रमन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का किया निरीक्षण

दौरा

- पुलिस मुख्यालय की ओर से नामित ऑफिसर आईजी विम्मी रमन ने हरिद्वार का दौरा किया

हरिद्वार/टीम एक्शन इंडिया
चारधाम यात्रा को सुचारु,सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से नामित नोडल ऑफिसर आईजी विम्मी सचदेवा रमन ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह,एसपी क्राइम व ट्रैफिक निशा यादव,एसपी सिटी अभय कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण,सुरक्षा व्यवस्था,पार्किंग और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रगति रिपोर्ट साझा की।
आईजी विम्मी सचदेवा रमन ने चारधाम यात्रा के लिए तैयार किए गए समग्र रोडमैप की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ इसे साझा करते हुए पार्किंग स्थलों,यात्रा पड़ावों और रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तैयार रोडमैप का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए,ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के पश्चात नोडल ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर पार्किंग स्थलों,हॉल्टिंग पॉइंट्स और रजिस्ट्रेशन सेंटर्स का भौतिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने तथा आवश्यक सुधार शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।

न्यूज फ्लैश

फ्लिपकार्ट और उबर की साझेदारीः अब रोजाना की राइड्स पर पाएं सुपरकॉइन्स

देहरादून । भारत के स्वदेशी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, फ्लिपकार्ट ने आज देश के एक प्रमुख मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, उबर के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत अब यूजर्स हर योग्य उबर राइड पर सुपरकॉइन्स कमा सकेंगे। यह पहल सुपरकॉइन्स को एक 'लाइफस्टाइल लॉयल्टी प्रोग्राम' के रूप में आगे बढ़ाती है, जिससे यूजर्स अपनी हर दिन की यात्रा पर भी रिवॉर्ड्स पा सकेंगे। यह फ्लिपकार्ट के एक व्यापक रिवॉर्ड इकोसिस्टम बनाने के विजन को मजबूती देता है और उबर के लिए ग्राहकों की हर दिन की राइड्स में अतिरिक्त वैल्यू जोड़ता है। अपने फ्लिपकार्ट और उबर अकाउंट को लिंक करके, यूजर्स हर योग्य राइड पर किराए का 4 प्रतिशत सुपरकॉइन्स के रूप में कमा सकते हैं। इसमें हर ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा 150 तक कॉइन्स मिल सकते हैं और कुल कमाई की कोई सीमा नहीं है। ये सुपरकॉइन्स सीधे यूजर के फ्लिपकार्ट अकाउंट में जमा हो जाते हैं, जिन्हें फ्लिपकार्ट मिनट्स, क्लियरट्रिप और अन्य पार्टनर प्लेटफॉर्म सहित पूरे फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम पर रिडीम किया जा सकता है।
इस साझेदारी के तहत कुछ सीमित समय के विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। नए उबर यूजर्स, या वे जिन्होंने पिछले 84 दिनों से ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, अकाउंट लिंक करने के 28 दिनों के भीतर अपनी पहली राइड पूरी करके 150 बोनस सुपरकॉइन्स कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो यूजर्स 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 के बीच अपने फ्लिपकार्ट और उबर अकाउंट को लिंक करेंगे और 28 दिनों के भीतर अपनी पहली राइड पूरी करेंगे, उन्हें 50 अतिरिक्त बोनस सुपरकॉइन्स भी मिलेंगे।
साझेदारी पर बात करते हुए, फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट (पेमेंट्स और सुपरकॉइन्स), गौरव अरोरा ने कहाः हम सुपरकॉइन्स को सिर्फ शॉपिंग तक सीमित न रखकर आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बना रहे हैं। यात्रा इसका एक अहम हिस्सा है, और उबर के साथ इस पार्टनरशिप से हम ग्राहकों के डेली रूटीन से और करीब से जुड़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य सुपर कॉइन्स का दायरा और बढ़ाना है ताकि ग्राहकों को हर जगह ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सकें।
उबर में इंडिया और दक्षिण एशिया के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर, अर्नब कुमार ने कहाः उबर में हमारा पूरा ध्यान ग्राहकों की रोजाना की यात्रा को और भी आसान और फायदेमंद बनाने पर है। फ्लिपकार्ट के साथ इस साझेदारी से हम अपने राइडर्स को बेहद सरल तरीके से अतिरिक्त लाभ दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य ग्राहकों के डिजिटल व्यवहार को समझना है, ताकि हम उनकी हर रोज की जरूरतों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए और भी आसान बना सकें।
यह साझेदारी दो बड़े और रोज इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लाती है, जिससे रिवॉर्ड्स का दायरा शॉपिंग से आगे बढ़कर यात्रा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुँच गया है। यह इस बात का संकेत है कि अब ग्राहकों को हर सेवा के साथ आसानी से ज्यादा मूल्य और फायदे देने पर जोर दिया जा रहा है।

परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मिले सनातन महापरिषद भारत संस्था के पदाधिकारी

देहरादून । सनातन महापरिषद भारत के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से यातायात की बढ़ती समस्या को लेकर वार्ता की ! संस्था के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष योगी महेंद्रनाथ ने बताया की संस्था सरकार के साथ हाथ मिलाकर राज्य में बढ़ती हुई यातायात की समस्या को कंट्रोल करने के लिये कार्य करना चाहती है ! इसके लिए उन्होंने अपना बनाया हुआ प्लान परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से साझा किया ! इस प्लान के तहत उत्तराखंड के ही बेरोजगार युवक युवतियों को संस्था द्वारा उन्हीं के ग्रह क्षेत्रों में रोजगार देकर भर्ती किया जायेगा,संस्था का यह प्लान पूरे उत्तराखंड में कार्य करेगा ! जिससे भविष्य में चार धाम यात्रा तथा विशेष स्नान वाले पर्व पर उत्तराखंड में बढ़ने वाली वाहनों की समस्या से निपटा जा सकता हैं ! संस्था इस कार्य के लिये होने वाले खर्च का बजट भी कुछ शर्तों के साथ स्वयं वहन करने को तैयार हैं !

एजीआई इंफ्रा लिमिटेड को ह्यूटोपिया बाय एजीआईह्ल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जीएमडीए लाइसेंस प्राप्त हुआ

टीम एक्शन इंडिया
देहरादून। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड (बीएसईः 539042, एनएसईः एजीआईआईएल), जो आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट विकास में विशेषज्ञता रखने वाली एक अग्रणी कंपनी है, ने घोषणा की है कि उसे ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) से अपनी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, ह्यूटोपिया बाय एजीआईह्ल के विकास के लिए लाइसेंस संख्या एलडीसी-101/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 प्राप्त हुआ है, जो न्यू चंडीगढ़ में कंपनी के पहले प्रोजेक्ट का प्रतीक है। लाइसेंस कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को प्राप्त किया गया था।
यह प्रोजेक्ट न्यू चंडीगढ़ के एक प्रीमियम आवासीय क्षेत्र में 10.26 एकड़ के भूखंड पर विकसित किया जाएगा। ह्यूटोपिया बाय एजीआईह्ल लगभग 31,93,697 वर्ग फुट का बिक्री योग्य क्षेत्र प्रदान करेगा और इसमें 3बीएचके, 4बीएचके और 5बीएचके इकाइयों सहित कई कॉन्फि गरेशन में 661 आवासीय फ्लैट शामिल होंगे, साथ ही निवासियों के लिए सोच-समझकर योजनाबद्ध सुविधाएं और सुख-साधन होंगे। प्रोजेक्ट मिक्स में 5बीएचके अपार्टमेंट की 189 इकाइयां, 4बीएचके अपार्टमेंट की 252 इकाइयां और 3बीएचके अपार्टमेंट की 220 इकाइयां शामिल हैं, जिससे कुल इन्वेंट्री 661 आवासीय फ्लैट हो गई है। ह्यूटोपिया बाय एजीआईह्ल न्यू चंडीगढ़ माइक्रो-मार्केट में एजीआई इंफ्रा लिमिटेड के रणनीतिक प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े पैमाने पर प्रीमियम हाउसिंग विकास के साथ इसके आवासीय प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। हाल ही में कंपनी ने लगभग 30 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से पहली किश्त के रूप में 12 करोड़ रुपये का निवेश किया और वर्ल्डनेक्स्ट रियल्टी एलएलपी में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। इससे पहले, कंपनी ने क्यूआईपी के माध्यम से 75 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें कई एफपीएल - क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी ह्न एलीट कैपिटल फंड, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी ह्न सिटाडेल कैपिटल फंड, बीकन स्टोन कैपिटल वीसीसी ह्न बीकन स्टोन 1, एस्टोर्न कैपिटल वीसीसी ह्न आवेन, एस्टोर्न कैपिटल वीसीसी ह्न अल्फा ए2 की भागीदारी देखी गई। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड पंजाब में एक अग्रणी रियल एस्टेट विकास और निर्माण कंपनी है, जो गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। जालंधर में मुख्यालय और लुधियाना व पंजाब के अन्य हिस्सों में मजबूत उपस्थिति के साथ, एजीआई इंफ्रा पंजाब रियल एस्टेट बाजार में एक भरोसेमंद नाम के रूप में उभरी है। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड जालंधर, लुधियाना और उससे आगे प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को वितरित करने के लिए प्रसिद्ध है

दो इनामी आरोपित गिरफ्तार

हरिद्वारः पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे सघन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के निर्देश पर नशा तस्करों, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वांछित, इनामी अपराधियों के खिलाफ लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पथरी पुलिस टीम की ओर से गुरूवार को उक्त थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वांछित अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान ग्राम इब्राहिमपुर में हुए एक झगड़े से संबंधित मामले में वांछित चल रहे दो इनामी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लक्की राणा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया

देहरादून । राजधानी देहरादून में आज उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्की राणा समेत कई कांग्रेस कार्यकताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तराखंड की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। विशेष बात यह रही कि लक्की राणा स्वयं हाथ में भारतीय संविधान लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ओएनजीसी चौक से पहले ही उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। यह घटना उस दिन हुई जब देशभर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी और बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया जा रहा था।
ज्ञापन में प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को उठाया गया था, जिनमें कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नशे का बढ़ता जाल, पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दे शामिल थे।
कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया और लक्की राणा सहित कई कार्यकताओं को हिरासत में लेकर कैंट कोतवाली ले जाया गया
हिरासत के दौरान एक और गंभीर आरोप सामने आया है। लक्की राणा ने बताया कि कैंट कोतवाली में पानी मांगने पर एक पुलिसकर्मी द्वारा उनके साथ अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किया गया।

खड़ी कार बनी आग का गोला, पूरी तरह जलकर खाक

हड़कंप

- सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

हरिद्वार/टीम एक्शन इंडिया
जनपद के सिविल लाइन रूड़की कोतवाली क्षेत्र स्थित सत्ती मोहल्ला के इंदिरा पार्क के पास बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक खाली प्लॉट में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और यूके 07 डी 3498 कार, जो मंगलौर निवासी फहीम की बताई जा रही है, जलकर खाक हो गई।
जानकारी के अनुसार, वाहन को उनके एक मित्र के घर के बाहर खड़ा किया गया था, तभी अचानक उसमें धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग पूरी कार में फैल गई। कॉलोनीवासियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी।
दमकल कर्मियों के अनुसार समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आसपास के वाहनों और मकानों तक नहीं फैल सकी। साथ ही कार में लगे पेट्रोल टैंक को भी फटने से बचा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
फायर विभाग के फायरमैन अतर सिंह राणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना की सूचना पर कार मालिक फहीम भी मौके पर पहुंचे और अपनी जली हुई कार देखकर स्तब्ध रह गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचता, तो आग आसपास के घरों और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी।

विश्व के सबसे ऊंचे शिवालय तुंगनाथ धाम बना आकर्षण का केंद्र

देहरादून/टीम एक्शन इंडिया
देवभूमि में समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का धाम दुनिया में सबसे ऊंचा शिशालय है। यह इन दिनों देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंचकेदारों में तृतीय स्थान रखने वाला यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता बल्कि अपनी अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी विश्व विख्यात है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के पश्चात आत्मग्लानि से मुक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए

पांडवों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। यहां भगवान शिव की बाहुओं (भुजाओं) की पूजा की जाती है। पत्थरों की अद्भुत स्थापत्य शैली से निर्मित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु असीम शांति का अनुभव करते हैं।
वर्तमान में ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में भक्त कठिन चढ़ाई पार कर बाबा तुंगनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी घाटी शिव के जयकारों से गुंजायमान है।
मखमली बुग्याल और दुर्लभ पुष्प
तुंगनाथ घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है। चारों ओर फैले हरे-भरे मखमली बुग्याल और उनमें खिले दुर्लभ प्रजाति के रंग-बिरंगे फूल किसी स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं हैं। घाटी की शीतल हवाएं और हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं।
चंद्रशिला शिखर : जहां राम ने की थी तपस्याह्न
तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला शिखर ट्रैकिंग के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि लंका विजय के पश्चात भगवान श्रीराम ने यहां एकांत में तपस्या की थी।
चोटियों से दिखता है हिमालय का 360 डिग्री नजारा
यहा से चौखम्भा, नंदा देवी, त्रिशूल और केदारनाथ जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के 360-डिग्री दर्शन होते हैं।
विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें चोटियों को स्वर्ण आभा से नहलाती हैं, तो वह दृश्य अविस्मरणीय होता है।

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता / प्रथम द्वारा ई टेन्डर जिनके बन्द होने की तिथि प्रत्येक निविदा के सामने अंकित है। निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	04-DRM-MB-26-27 Dt. 13.04.2026	09-DRM-MB-26-27 Dt. 15.04.2026	10-DRM-MB-26-27 Dt. 15.04.2026	11-DRM-MB-26-27 Dt. 15.04.2026	12-DRM-MB-26-27 Dt. 15.04.2026
कार्य का नाम	Upgradation of crew and train manager lobby at LRJ and DDN & running room at Dehradun	Improvement of roads and other Flooring upgradation at various stations (FROM LRJ TO RKSH) LRJ, ATMO, PRI, IKK, JWP, HW, RWL, MOTC & RKSH etc under Sr DEN 1 MB.	Construction of boundary wall to prevent of Heavy encroachment & tress passing between Jwalapur – Haridwar/ HW-MOTC under Sr DEN 1 MB.	Improvement of LC road surface by providing Rubberized Surface at LC No. 14,18,19,20,30, 37, 39 & 41 in the sec. of Sr.DEN/I/MB.	Drainage improvement in LRJ yard under ADEN/RK
निविदा का प्रकार	Works	Works	Works	Works	Works
निविदा की कीमत	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
अनुमानित लागत (रु.)	98,17,414.91	8,09,39,284.42	2,34,26,449.63	1,39,61,757.62	2,00,49,300.00
धरोहर राशि (रु.)	1,96,400.00	16,18,800.00	4,68,500.00	2,79,200.00	4,01,000.00
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक / समय	08.05.2026 16:00	08.05.2026 16:00	08.05.2026 16:00	08.05.2026 16:00	08.05.2026 16:00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	24.04.2026	24.04.2026	24.04.2026	24.04.2026	24.04.2026
आफर की वैधता	60 Days	60 Days	60 Days	60 Days	60 Days
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 Months	06 Months	06 Months	06 Months	06 Months

नं. 74-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 16.04.2026 1265/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर भारत
देहरादून, 17 अप्रैल 2026
दैनिक एक्शन इंडिया
www.actionindialive.com
ACTION INDIA

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिलाई शपथ, सुशासन पर दिया जोर

भजनलाल शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आान किया

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर : शासन सचिवालय में गुरुवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निकाय है, जहां से नीतियों और योजनाओं का निर्माण कर उन्हें धरातल पर लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करें, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है और इसका सीधा लाभ आमजन को मिलता है। समारोह में मुख्यमंत्री ने संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा सहित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने ह्यमिशन कर्मयोगीह्न का उल्लेख

करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भवः होना चाहिए, जिससे आमजन के जीवन स्तर में निरंतर सुधार संभव हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले सवा दो वर्षों में कर्मचारी कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इनमें ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई, कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, आरजीएचएस के तहत माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प, अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू को शामिल

आवश्यकता अनुसार पद सृजन के प्रस्ताव का आदेश जारी

सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नए पदों के अतिरिक्त 15 और पद सृजित किए जाएंगे, पदोन्नति से वंचित काडर के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, मुख्य सचिव को विभिन्न विभागों में आवश्यकता अनुसार पद सृजन के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने सुशासन, जवाबदेही और जनसेवा को प्रशासन की आधारशिला बताते हुए कर्मचारियों से दक्षता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आान किया।

किया गया, महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को 6 चरणों में स्वीकृति, मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन की स्थापना से कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट वर्ष 2026-27 में कार्मिकों और पेंशनर्स के हित में दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। साथ ही अधिकारियों को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि, पेयजल, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और युवाओं के लिए नई युवा नीति लागू की गई है। अब तक 1.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और इतनी ही नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सचिवालय कार्मिकों के

राजस्थान के स्कूलों में विद्यार्थियों के अजीब नाम बदलने

जयपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों के "घसीटाराम", "भालू सिंह", 'घासी राम", "मक्खी सिंह", जैसे अजीब नाम बदलने के लिए पहल की है। "सार्थक नाम अभियान" शुरू किया गया है और शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को 2950 शब्दों की एक सूची भेजकर कई नाम सुझाए हैं। निर्देश हैं कि प्रधानाध्यापक अजीब नाम वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सहमति से सूची में से कोई एक नाम संबंधित विद्यार्थी का रख सकेंगे। इस अभियान में अब तक करीब डेढ़ हजार विद्यार्थियों के नाम बदले जा चुके हैं। अजीब नाम वाले विद्यार्थियों को कई बार स्कूल में हीनभावना का सामना करना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के सरकारी रिकार्ड में नाम बदलने को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। हालांकि, शिक्षा विभाग द्वारा नामों की भेजी सूची में भी कई ऐसे नाम सुझाए गए हैं, जिनमें व्याकरण की गलती है। जैसे असम नाम सुझाया गया है, जबकि सही शब्द आसिम है। सुझाए गए नामों की सूची में रोनक, संतोख, तारचंद जैसे नाम हैं, जबकि सही नाम रौनक, संतोष व ताराचंद हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व, संस्कार और सामाजिक छवि का दर्पण होता है।

जनगणना देश के विकास की नींवः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 16 अप्रैल से प्रदेश में जनगणना का शुभारंभ हो रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है। जनगणना देश की रीढ़ है, यह विकास की नींव है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ . यादव ने गुरुवार को प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व-गणना पोर्टल पर प्रारंभिक पंजीकरण कर प्रदेश में स्व-गणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ हो रही है। प्रदेशवासियों को इसमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ भाग लेना चाहिये। यह जनगणना हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक ऑनलाईन स्व-गणना का कार्य होगा। एक से 30 मई तक मकान सूचीकरण होगा। यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी।

जनगणना

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का ऑनलाईन शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है। इससे हम जान सकेंगे कि विकास की धारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुगमता से पहुंच रही है या नहीं। यह जनगणना हमारी अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जनगणना में वह सही, सटीक और पूर्ण जानकारी दे। जनगणना में लगे कर्मचारी-अधिकारी राष्ट्र निर्माण का पवित्र कार्य कर रहे हैं। उनका परिश्रम और सटीकता से किया गया कार्य देश के भविष्य को मजबूत बनाएगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त भोपाल नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, जनगणना संचालनालय के डिप्टी रजिस्टार जनरल डॉ. विजय कुमार सहित जिला प्रशासन और जनगणना संचालनालय के अधिकारी उपस्थित थे।

बिरला स्टुडियोज ने वी के साथ की साझेदारी

टीम एक्शन इंडिया

शिमलाः बिरला स्टुडियोज ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के सहयोग से आज अपनी तरह के पहले मोबाइल-फर्स्ट टेलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म रील से रियल स्टार के लॉन्च की घोषणा की है, जिसे भारत के एंटरटेनमेन्ट उद्योग में प्रवेश को एक समान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रतिभा को पहचानने के दृष्टिकोण के साथ रील से रियल स्टार भूगोल, पहुंच एवं उद्योग जगत के साथ कनेक्शन जैसी पारम्परिक बाधाओं को दूर करता है तथा हर उस व्यक्ति के लिए सिनेमा के रास्ते खोलता है, जिसके पास स्मार्टफोन है। अनन्या बिरला, संस्थापक एवं चेयरपर्सन, बिरला स्टुडियोज ने कहा, ह्यरील से रियल स्टार के माध्यम से हम ऐसे मंच का निर्माण करना चाहते हैं, जहां किसी भी स्थान से आने वाली प्रतिभा को पहचाना जाए और उन्हें मिलने वाले अवसर सिर्फ परिस्थितियों से सीमित न रहें। क्योंकि हर किसी को हक है कि उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए, आगे बढ़ने के उचित अवसर दिए जाएं। वोडाफोन आइडिया की डिजिटल पहुंच और बिरला स्टुडियोज के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उपयोग कर यह मंच भारत की असली एवं विविध अभिनय प्रतिभा को मुख्यधारा के एंटरटेनमेन्ट जगत के साथ जोड़ती है।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्रीहरिमंदिर जी परिसर, पटना साहिब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तख्त श्रीहरिमंदिर जी, पटना साहिब में मत्था टेका और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, स्कूटी से ले जानी पड़ी लाश, अस्पताल में इलाज न मिलने का आरोप

टीम एक्शन इंडिया

सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बेहद संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। यहां इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों को शव स्कूटी पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय रामसजीवन गुप्ता की तबीयत बुधवार रात करीब 11 बजे अचानक बिगड़ गई थी। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां न तो डॉक्टर मौजूद थे और न ही कोई जिम्मेदार स्टाफ। परिजन मदद के लिए भटकते रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल सका और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मौत के बाद भी परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। अस्पताल प्रशासन ने ना ही एंबुलेंस उपलब्ध कराई और ना ही शव वाहन की व्यवस्था की। मजबूरन परिजन रामसजीवन गुप्ता का शव स्कूटी पर रखकर घर ले गए। अस्पताल गेट पर मौजूद महिलाएं रोती-बिलखती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एसीसी गग्गल में अदाणी फाउंडेशन की पहल, एएसडीसी बदल रहा है युवाओं की जिंदगी

टीम एक्शन इंडिया

शिमलाः विविध क्षेत्रों में कार्यरत अदाणी पोर्टफोलियो की कंपनी एसीसी तथा अदाणी फाउंडेशन,एसीसी गग्गल स्थित अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एएसडीसी) के माध्यम से मंडी जिले के ग्रामीण युवाओं को कौशल,आत्मविश्वास और रोजगार सहायता प्रदान कर उन्हें भारत के तेजी से बढ़ते रिटेल क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर दे रहे हैं।मंडी के किसी छोटे से गांव से निकलकर मोहाली के एक बड़े रिटेल स्टोर तक पहुंचने के लिए आखिर क्या चाहिए? शायद सही प्रशिक्षण और कोई ऐसा जो आप पर विश्वास करे।बरोटी की पल्लवी शर्मा और सिहाल के महेश्वर सिंह के लिए यह विश्वास बना अदाणी फाउंडेशन का एएसडीसी,एसीसी गग्गल,जिसने उन्हें केवल कौशल ही नहीं दिया,बल्कि यह एहसास भी कराया कि वे जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।दोनों ने जब एएसडीसी गग्गल में रिटेल सेल्स एसोसिएट कोर्स में दाखिला लिया,तो यह एक तरह से खुद पर भरोसे का फैसला था।

'लखपति दीदी' पहल से ग्रामीण महिलाए बनीं आत्मनिर्भर

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी पहल उल्लेखनीय परिणाम दे रही है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुंचाना है। जनसंपर्क अधिकारी आर.आर. पटेल ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने आगामी दो वर्षों में 16.41 लाख परिवारों को लखपति दीदी बनाने

का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 12.49 लाख महिलाएं इस श्रेणी में पहुंच चुकी हैं, जो इस योजना की सफलता को दशार्ता है। इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 526 मास्टर ट्रेनर और 20 हजार 517 लखपति सीआरपी (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित कर्मी महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के साथ उनकी आय-व्यय योजना तैयार करने और वित्तीय एवं

वार्षिक आय

- आगामी दो वर्षों में 16.41 लाख परिवारों को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य

तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को कम से कम दो या अधिक आय स्त्रोतों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे जोखिम कम हो और आय में स्थिरता बनी रहे।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने छठवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक फायदा मिलेगा, साथ ही लंबित एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जनसंपर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि नई दरों के मुताबिक महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। हालांकि इसका वास्तविक भुगतान 1 अप्रैल 2026 से (मई 2026 के वेतन) के साथ शुरू होगा। इसके अलावा, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों को 6 समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 के बीच दिया जाएगा,

भुगतान

- महंगाई भत्ता बढ़कर 257%, एरियर का भी होगा भुगतान, प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी की गई बढ़ोतरी

जिससे उन्हें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक लाभ मिलेगा।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों या उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके। महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। साथ ही, यह भी साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते को किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

सीएम सम्राट पहुंचे सचिवालय, अधिकारियों के साथ की बैठक, विजय चौधरी ने संभाला पदभार

टीम एक्शन इंडिया

पटना। मुख्यमंत्री बनने के सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं । गुरुवार सुबह सम्राट सचिवालय पहुंच और सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक की । बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ जदयू के विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने भी शपथ ली थी। फिलहाल राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मौजूदा व्यवस्था के तहत

जिम्मेदारी

- उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण किया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग हैं, जबकि विजय चौधरी को 10 और बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद इन विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा। तब तक तीनों नेता ही सभी विभागों का कार्यभार संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई भवन स्थित जल संसाधन विभाग में

पदभार ग्रहण किया एवं विभागीय कार्यों का जायजा लिया। विभागीय प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिया भरोसा, बिहार की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं होगी

बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखकर खुशी साझा की। उन्होंने कहा है कि यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का है। ऊर्जावान, लोकप्रिय एवं कर्मठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पत्र में सभी कार्यकर्ताओं का ' जय श्रीराम' के जरिये अभिवादन करते हुए यह भी बताया कि यह दशकों के अथक परिश्रम, त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। उन्होंने इसके लिए बूथ से लेकर प्रदेश तक हर कार्यकर्ता को श्रेय देते हुए कहा कि उनके समर्पण ने इस गौरवशाली क्षण को संभव बनाया है। उन्होंने साथ ही जनता दल (यूनाइटेड) के विजय कुमार चौधरी एवं बिजेन्द्र प्रसाद यादव के उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण पर भी हार्दिक बधाई दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार को बिहार के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय बताते हुए पत्र में लिखा है - हम विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए गर्व अनुभव करते हैं कि पहली बार बिहार में सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के हाथों में है। उन्होने इसे परिवर्तन नहीं, यह निरंतरता बताते हुए दावे के साथ कहा कि सुशासन की उसी नींव पर, उसी प्रतिबद्धता के साथ, अब और अधिक संकल्प एवं ऊर्जा के साथ बिहार के विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा - पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुदृढ़ नींव पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल मार्गदर्शन में बिहार के विकास को हम नई गति देंगे। सुशासन से समृद्धि युग, बिहार अभ्युदय काल का शुभारंभ हो चुका है।

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में नई सरकार की अनिवार्यता का विमर्श

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से एक व्यापक सामाजिक, वैचारिक और लोकतांत्रिक संघर्ष का मंच रही है। इस बार भी 2026 के विधानसभा चुनाव इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब यह चुनाव ही तय करेगा कि राज्य में लोकतंत्र की गुणवत्ता, जवाबदेही और संस्थागत मजबूती किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसे परिदृश्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। दरअसल, पिछले एक दशक में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण देखने को मिला है। 2011 में परिवर्तन की उम्मीदों के साथ सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने शुरूआत में जनसमर्थन अर्जित किया, लेकिन समय के साथ यह शासन शैली एक व्यक्ति-केन्द्रित प्रशासन में बदलती चली गई। प्रशासनिक निर्णयों में संस्थाओं की भूमिका सीमित होती गई और राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र के बीच की दूरी कम होकर पक्षपातपूर्ण होते हुए दिखी। हालांकि ममता का राज इसी विश्वास पर बहाल हुआ था कि पश्चिम बंगाल से अराजकता की समाप्ति होगी, बांग्लादेश से होनेवाली घुसपैठ रुकेगी और हिंसा बंद होकर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर हकीकत में क्या हुआ? यही कि वादों के अनुरूप ममता सरकार कुछ नहीं कर पाई, उल्टा यह सामने आया कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही समाप्त हो गई। ममता सरकार अपनी हर आलोचना को दबाने लगी। विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया गया और प्रशासनिक मशीनरी को राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वभाविक है कि सभी संकेत लोकतंत्र के लिए खतरे के हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ जघन्य अपराध हम सभी ने देखा, कैसे एक प्रशासनिक संवेदनहीनता और जवाबदेही के अभाव का प्रतीक बन कर सामने आया है। ऐसे मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया ने यह संदेश दिया कि ममता सरकार जनता की सुरक्षा से अधिक अपनी छवि बचाने में रुचि रखती है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक हिंसा की घटनाएं, जोकि बंगाल की राजनीति का एक पुराना दाग रही हैं, अब भी समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि कहना चाहिए ममता राज आने के बाद इसमें बढ़ोत्तरी ही हुई है। चुनावी प्रक्रिया में हिंसा, विपक्षी कार्यकताओं पर हमले और मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं किंतु इस बात की फिकर किसे है! ममता का अपना अब तक फिक्स हो चुका वोट का चुनावी गणित है। इसलिए ही ममता सरकार की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक उसकी वोट बैंक आधारित राजनीति रही है। यहां उल्लेखित है कि राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 28-29 फीसद है और लंबे समय तक एकमुश्त वोटिंग के कारण यह एक निर्णायक राजनीतिक कारक बनी रही है। कहना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ने इस समीकरण को कुशलता से साध रखा है, किंतु इसके परिणामस्वरूप नीति-निर्माण में संतुलन की कमी दिखाई देती है।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

अंकों की दौड़ नहीं, समझ और संतुलन की जरूरत

-सुनील कुमार महला

> पाठकों को बताता चलूं कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जॉन बी. वॉटसन ने बच्चों के विकास को लेकर एक चर्चित और विवादास्पद कथन दिया था-मुझे एक दर्जन स्वस्थ, अच्छी तरह विकसित शिशु दे दीजिए और उन्हें अपने वातावरण में पालने का अवसर दीजिए, तो मैं उनमें से किसी को भी डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी, यहां तक कि भिखारी या चोर बना सकता हूं, चाहे उसकी जन्मजात प्रतिभा कुछ भी क्यों न हो। वास्तव में, इस कथन का मूल भाव यह है कि वे बच्चों के विकास में वातावरण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे

हाल ही में, बुधवार को 15 अप्रैल 2026 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें इस वर्ष कुल 93.70% छात्र सफल हुए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 93.66% की तुलना में 0.04% अधिक है, जो परिणाम में हल्का किंतु सकारात्मक सुधार दशार्ता है। इस बार भी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 94.99% पास प्रतिशत हासिल किया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.69% रहा। वहीं ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत 87.50% दर्ज किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी और प्रगति का संकेत देता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में 55,368 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 2,21,574 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, जो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और विद्यार्थियों की मेहनत को दशार्ता है। इसके साथ ही लगभग 14.7 लाख से अधिक छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, जो यह दशार्ता है कि एक बड़ा वर्ग अभी भी सुधार की दिशा में प्रयासरत है। इस वर्ष परीक्षार्थियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम रही। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई ने इस बार भी टॉपर सूची जारी नहीं की और न ही फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन की व्यवस्था अपनाई, ताकि छात्रों के बीच अनावश्यक तुलना और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। हालांकि, परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रवृत्ति भी सामने आती है, जहां अभिभावक अपने बच्चों के अंकों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे बच्चों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। वास्तव में, हर बच्चा अलग होता है- किसी की गणित और विज्ञान में पकड़ मजबूत होती है तो कोई कला, खेल या भाषा में उत्कृष्ट होता है। यदि बच्चों का मूल्यांकन केवल अंकों के आधार पर किया जाए, तो इससे उनके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वे हीन भावना, तनाव तथा असफलता के भय से ग्रस्त हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा अवश्य है, लेकिन वह तभी तक सकारात्मक है जब तक वह प्रेरणा

देती है; जब यह दबाव और चिंता का कारण बनने लगे, तब यह मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए बच्चों को दूसरों से बेहतर बनने के बजाय स्वयं से बेहतर बनने की प्रेरणा देना अधिक उचित है। इस संदर्भ में माता-पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें बच्चों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, न कि केवल परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा अपेक्षा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे डांटने या तुलना करने के बजाय यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सुधार की आवश्यकता कहां है। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना, उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझना तथा उसी दिशा में प्रोत्साहित करना ही सही मार्गदर्शन है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब अभिभावक अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं, तो यह उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा बनती हैं। हर बच्चा अपनी अलग पहचान और क्षमता लेकर आता है, इसलिए उस पर अत्यधिक अपेक्षाओं का बोझ डालना उचित नहीं है। हाल फिलहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि अंकों की अंधी दौड़ बच्चों के समग्र विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सफलता का वास्तविक पैमाना केवल अंक नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और प्रतिभा का विकास है। अत्यधिक दबाव के कारण बचपन प्रभावित हो रहा है और रचनात्मकता में कमी आ रही है, जबकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जॉन बी. वॉटसन ने बच्चों के विकास को लेकर एक चर्चित और विवादास्पद कथन दिया था-मुझे एक दर्जन स्वस्थ, अच्छी तरह विकसित शिशु दे दीजिए और उन्हें अपने वातावरण में पालने का अवसर दीजिए, तो मैं उनमें से किसी को भी डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी, यहां तक कि भिखारी या चोर बना सकता हूं, चाहे उसकी जन्मजात प्रतिभा कुछ भी क्यों न हो। वास्तव में, इस कथन का मूल भाव यह है कि वे बच्चों के विकास में वातावरण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान यह मानता है कि बच्चे के व्यक्तित्व और विकास में वंशानुगत गुण (हेरिडिटेरी ट्रेट्स) और वातावरण-दोनों का संतुलित योगदान होता है। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दशार्ता है कि सही माहौल और सकारात्मक प्रोत्साहन से बच्चों को बेहतर दिशा दी जा सकती है, न कि केवल दबाव डालकर। वास्तव में, हम सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे वास्तव में कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जिन्हें जिस दिशा में मार्गदर्शन मिलता है, वे उसी रूप में ढलते चले जाते हैं। उनका मन कोमल, जिज्ञासु और सीखने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें बचपन से ही सही संस्कार, संयम और सकारात्मक सोच दी जाए। यदि बच्चों में संयम विकसित किया जाए, तो वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचते हैं। इसके साथ ही आत्मविश्वास का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वासी बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करते हैं। जब माता-पिता और शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं और असफलताओं में उनका साथ देते हैं, तब उनके भीतर एक मजबूत आत्मबल विकसित होता है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हम बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखें, बल्कि उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ध्यान दें। सही दिशा, स्नेह और अनुशासन का संतुलन ही उन्हें एक सफल और जिम्मेदार इंसान बना सकता है। वर्तमान समय में परीक्षा का दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया है, जहां अच्छे अंक लाने और दूसरों से आगे निकलने की होड़ बच्चों को मानसिक तनाव और चिंता की ओर धकेल रही है। कई बच्चे पढ़ाई को सीखने की प्रक्रिया के बजाय केवल अंक प्राप्त करने का साधन मानने लगते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। यदि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वह किसी भी सफलता का वास्तविक आनंद नहीं ले सकता। कहना गलत नहीं होगा कि आज सफलता की परिभाषा भी बदल रही है। अब केवल अच्छे अंक ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि रचनात्मकता, संचार कौशल, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन जैसे गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि बच्चों से अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उनका संतुलित और यथार्थवादी होना जरूरी है। बच्चों को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि वे संवेदनशील और असीम संभावनाओं से भरे इंसान हैं। यदि उन्हें सही वातावरण, समझ और प्रोत्साहन मिले, तो वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।

जनसंख्या बनाम विकासः लोकसभा पुनर्गठन की असली चुनौती

प्रो. आरके जैन

भारत की संसदीय व्यवस्था इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां लिया गया निर्णय आने वाले दशकों की राजनीति, नीतियों और प्रतिनिधित्व की दिशा तय करेगा। लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 (815 राज्य व 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) करने का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के गणित और भूगोल—दोनों को बदलने वाला कदम है। सवाल सीधा है, पर इसका उत्तर जटिल—क्या इससे आम मतदाता की ताकत वास्तव में बढ़ेगी या बड़े राज्यों का राजनीतिक प्रभाव और गहरा होगा? यही वजह है कि यह बहस अब संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर उस नागरिक तक पहुंच गई है, जो चाहता है कि उसका वोट सिर्फ गिना ही नहीं, बल्कि असर भी दिखाए।

सरकार का तर्क सीधा और ठोस है कि बढ़ती आबादी के साथ प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाना अब अनिवार्य हो चुका है। मौजूदा स्थिति में एक सांसद पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ है, जिससे स्थानीय समस्याएं अक्सर राष्ट्रीय बहस में दब जाती हैं। प्रस्तावित योजना के तहत सीटों को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर अधिकतम 850 करने से प्रत्येक सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे जनता और प्रतिनिधि के बीच दूरी घटेगी, संवाद सशक्त होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे नीतियों का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। साथ ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने के लिए यह विस्तार एक ठोस आधार के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीति में लैंगिक संतुलन को मजबूत कर सकता है। इस प्रस्ताव का एक ऐसा पक्ष भी है, जो गहरी चिंता पैदा करता है और जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों ने लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसका असर यह होगा कि दक्षिण के राज्यों का संसद में सापेक्षिक प्रभाव घट सकता है। यह स्थिति एक असंतुलन पैदा करती है, जहां विकास और बेहतर शासन का परिणाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी बनकर सामने आता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी, फिर भी दक्षिण के राज्यों को अपने प्रभाव में कमी की आशंका है।

यदि इसे आम नागरिक की नजर से परखा जाए, तो इस बदलाव के भीतर कई ठोस संभावनाएं दिखाई देती हैं। सीटों में वृद्धि का मतलब है कि संसद में अधिक विविधता आएगी और अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से उठ सकेंगी। ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पिछड़े वर्गों को अपनी बात रखने के लिए व्यापक मंच मिलेगा। महिला आरक्षण के जरिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

विचार

नारी शक्ति वंदन : आधी आबादी को पूरा हक, अब बदलेगी राजनीति की तस्वीर

मदन मोहन छाबड़,
प्रदेश सह संयोजक, एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक क्षण आया है जब आधी आबादी को केवल मतदाता नहीं, बल्कि सत्ता की साझीदार बनने का संवैधानिक अधिकार मिला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय राजनीति को दिशा को बदलने का सशक्त प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन वाली सरकार ने आधी आबादी को पूरा हक देते हुए उन्हें विकास की सहभागी नहीं, बल्कि विकास की दिशा देने का नेतृत्वकर्ता बनाने का फैसला लिया है, जोकि विकसित भारत के मिशन को नई गति देगा। नारी शक्ति वंदन के जरिए अब देश की बेटियां और बहनें नीतियों की दर्शक नहीं, बल्कि निमार्ता बनेंगी। यह बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और लोकतंत्र को अधिक संतुलित, न्यायपूर्ण और सशक्त बनाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की राजनीति में एक नई तस्वीर उकेरने जा रहा है जहां आधी आबादी की सत्ता में बराबरी होगी और विकास की धारा हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचेगी।

नारी वंदन अधिनियम संसद और विधानसभाओं के दरवाजे महिलाओं के लिए व्यापक रूप से खोलते हुए उन्हें नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह केवल 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि उस सोच में परिवर्तन की शुरुआत है। इससे न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि निर्णयों में संवेदनशीलता, समावेशिता और जमीनी वास्तविकताओं का समावेश भी सुनिश्चित होगा। हालांकि, भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है जिस से गांवों में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों के साथ विकास कार्यों से तस्वीर बदल रही है। आज लोकसभा में केवल 15 प्रतिशत और विधानसभाओं में औसतन 9 प्रतिशत महिलाएं हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण से लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से बढ़कर 181 से अधिक हो जाएगी। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब संसद-विधानसभा में भी महिलाओं की आवाज मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मान-सम्मान का जो अभियान पिछले 11 वर्षों से चलाया हुआ है वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने महिला-नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर भी प्रमुखता से रखा है। उनका मानना है कि विकसित भारत का सपना नारी शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। 50 प्रतिशत आबादी जब नीति-निर्माण में सीधे भाग लेगी, तो देश की जीडीपी मानव विकास सूचकांक दोनों बेहतर होंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण की दिशा और गुणवत्ता दोनों में बदलाव आएगा। महिलाएं समाज के विभिन्न पहलुओं विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, लैंगिक समानता और बाल विकासकृसे जुड़ी चुनौतियों को अधिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझती हैं। जब वे संसद और विधानसभाओं में अपनी आवाज बुलंद करेंगी, तो नीतियों में समावेशिता और सामाजिक न्याय की भावना और मजबूत होगी। 2029 का चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा, जब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां संसद के गलियारों में बैठकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में निर्णय लेंगी। यह अधिनियम नए भारत की उस उड़ान का प्रतीक है जिसकी गति अजेय है और जिसका लक्ष्य परम वैभव है। वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का प्रयास हुआ। वे घर की चारदीवारी तक सीमित कर दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखी गईं। फिर भी रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, चांदबीबी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कुछ नारियों ने इस काल में भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमता की छाप छोड़ी है।

आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाने में 100 से अधिक महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका को आज कौन नहीं जानता। साफ जाहिर है कि महिलाओं को जब भी अवसर दिया गया, उन्होंने स्वयं को साबित कर दिखाया। राजनीतिक सशक्तिकरण का सीधा प्रभाव सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर पड़ता है। जब महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति मिलती है तो उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। इससे परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को नया सम्मान मिलता है। वे संपत्ति, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों में भी कमी आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि सशक्त महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और मुखर होंगी। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं इनमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि। इन योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन सभी प्रयासों को एक नई दिशा और गति प्रदान करेगा, क्योंकि अब महिलाएं स्वयं इन योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भाग लेंगी। पहले यह कानून कई दशकों से लटकाया गया। पहले की सरकारों ने इसे केवल चर्चा तक सीमित रखा, लेकिन कभी भी इसे लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। कभी जातिगत आरक्षण के नाम पर, कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते, इस महत्वपूर्ण कानून को टालते रहे। 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद कई बार प्रयास हुए, बहसें हुईं विरोध और समर्थन के स्वर उठे, परंतु अंतिम निर्णय तक बात नहीं पहुंच सकी। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम के साथ देश की करोड़ों माताओं-बहनों के सपनों की जीत है।

नारी वंदन अधिनियम वास्तव में सशक्त नारी-सशक्त राष्ट्र के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआईः UTTHIN / 2009 / 31653

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, 7/1, बल्लूपुर रोड, डॉ टीपी पटनायक के सामने, कृष्ण नगर चौक के पास, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
स्थानीय संपादक : हिमांशु अनिकेत (9837313943)

'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

actionindiaddn@gmail.com

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

झोली वाले बाबाओं से सावधानी जरूरी

डॉ. सत्यवान सौरभ

उत्तर भारत के गाँवों में गेहूँ की कटाई केवल एक मौसम नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव होती है। यह वह समय है जब किसान की महीनों की तपस्या, धूप में जले हाथ, सर्द रातों की पहरेदारी और अनिश्चित मौसम के साथ लड़ी गई जंग अंततः रंग लाती है। खेतों में झूमती सुनहरी बालियाँ किसी साधारण फसल का दृश्य नहीं, बल्कि आशा, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक होती हैं। जब यही फसल कटकर घर के आँगन में ढेर बनाती है, तो वह केवल अनाज नहीं होती—वह पूरे साल की सुरक्षा होती है, बच्चों की पढ़ाई का आधार, बीमारियों में सहारा, और भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत होती है। घर की महिलाएँ उस अनाज को सहेजती हैं, साफ करती हैं, सुखाती हैं और बड़े जतन से उसे भंडार में रखती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यही दाने आने वाले समय में घर की नींव को मजबूत बनाए रखेंगे। लेकिन इस सुनहरे और संतोष भरे दृश्य के साथ ही एक ऐसी परछाईं भी गाँव की गलियों में उतरने लगती है, जो धीरे-धीरे इस खुशी को कम करने लगती है। यह परछाईं है झोली लेकर घूमने वाले तथाकथित बाबाओं और मोड़ों की, जो इसी मौसम का इंतजार करते हैं। जैसे ही अनाज घरों में आता है, ये लोग अचानक गाँवों में दिखाई देने लगते हैं। उनके वस्त्र, उनका रूप और उनकी वाणी सब कुछ इस तरह से रचा गया होता है कि वे श्रद्धा के पात्र प्रतीत हों। माथे पर तिलक, सिर पर पटका या टोपी, रंग-बिरंगे कपड़े और हाथ में एक झोली—यह सब मिलकर एक ऐसा रूप तैयार करते हैं, जिसे देखकर सामान्य ग्रामीण सहज ही प्रभावित हो जाता है। वे घर-घर जाकर दरवाजे पर खड़े होते हैं और मीठे शब्दों में आशीर्वाद देते हैं—भगवान भला करेगा माता रानी कृपा बनाए रखे—और बदले में कुछ अनाज या पैसे की अपेक्षा रखते हैं। गाँवों में दान और सेवा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है, जो आपसी सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत करती है। खासकर महिलाएँ इस परंपरा को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक तूफान

रोहित माहेश्वरी

संसद के विशेष सत्र में 16 अप्रैल को महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किये गये। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संशोधन विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वर्तमान में यह संख्या 543 है। जो विधेयक पेश किये गये हैं वो हैं, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026, संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 । प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों में अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। सीटों के अंतिम निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन विधेयकों पर संसद में 18 अप्रैल तक विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इन बिलों का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, एआईएमआईएम, सीपीआई एम समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्ष इसको बीजेपी की चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहा है। हालांकि पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं। इस दौरान सीट बढ़ाने के स्ट्रेट जैकेट फॉमूर्ला पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूदा सीटों को बढ़ाकर नए ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर करीब 800 से ज्यादा हो सकती हैं। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर ऐतराज किया है। इसलिए सरकार अब ऐसा फॉमूर्ला लाने की कोशिश कर रही है, जिससे सभी राज्यों के हितों का संतुलन बना रहे।

स्व-जन गणना सुविधा : ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर भरें विवरण

स्व-गणना

- नागरिक स्व-गणना प्रक्रिया में लें भाग, स्वगणना पोर्टल पर स्वयं भी दी अपनी जानकारी

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। उपायुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिक स्वयं भी अपनी जनगणना कर सकेंगे। आमजन 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण भर सकेंगे। स्व गणना के माध्यम से नागरिक अपनी जानकारी स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए है, जो किसी कार्यवश दिन भर अपने घरों से दूर रहते हैं।

उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जनगणना 2027 को लेकर प्रैस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं भी स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपना विवरण भरा। उन्होंने कहा कि यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा, जिसे 1 से 30 मई तक कराया जाना प्रस्तावित है। इस चरण के अंतर्गत गांवों एवं शहरों के आवासीय, गैर-आवासीय तथा सह-आवासीय भवनों की गणना की जाएगी। इसी प्रकार दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश एवं जनता के कल्याण के लिए नीतियों एवं योजनाएं बनाने के लिए अनिवार्य है। इसमें हर भवन हर व्यक्ति की गणना होना अनिवार्य है, क्योंकि यही आंकड़े विकसित भारत के निर्माण के लिए आधार बनेंगे। इसी के आधार पर शिक्षा, आवास एवं घरेलू, सुविधाएं प्रदान करना एवं अनेक कल्याणकारी योजनाएं सम्मिलित है। जनगणना में दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पूर्ण रूप से गोपनीय है। नागरिकों की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और नागरिक निस्संकोच होकर अपनी जानकारी प्रगणक को दें और देश के विकास का हिस्सा बनें।

उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है, जिसके लिए नागरिक गूगल पर सेल्फ एनुमरेशन टाईप करें और घर के मुखिया के नाम व मोबाइल से लॉग इन करें, जिससे एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस के बाद भाषा का चयन करें। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के साथ 14 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इसके बाद नागरिक गूगल मैप पर अपने राज्य, जिला व पिन कोड को डालते हुए अपने घर को मैप पर लोकेट करें।

अपने घर की लोकेशन कन्फर्म करते ही पहले चरण के सभी प्रश्न खुल जाएंगे। ये 27 प्रश्न मकान की स्थिति, घर में कुल लोगों की संख्या, घर के मुखिया की जानकारी, पेयजल का स्रोत, घर में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोटरसाइकल, कार का होना आदि के बारे में हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। इनका जवाब देने के बाद जब सबमिट करने पर मैसेज या ईमेल के द्वारा एक स्वगणना आईडी की प्राप्ति होगी, जो कि प्रगणक के घर आने पर, उसे देनी होगी। आईडी द्वारा सभी प्रश्नों का जवाब प्रगणक के पास आ जाएंगे और इसके सत्यापन के बाद वह इसे सबमिट कर देगा।

उपायुक्त ने सभी सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, महापौर और नगर निगम के सदस्य, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ब्लॉक समिति और उनके सदस्य, सभी पंच व सरपंच, सभी सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी एवं सभी युवाओं, सभी किसानों, छोटे-बड़े सभी व्यापारी गण एवं सभी आम आदमी से अपील की कि वे अपनी गणना 16 अप्रैल से स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिक स्वयं कर सकेंगे अपनी जनगणना: अनुभव मेहता

जनगणना

- जनगणना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा का अधिक उपयोग करें आमजन

टीम एक्शन इंडिया

लाडवा, 16 अप्रैल (विजय कौशिक) : एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिक स्वयं अपनी जनगणना कर सकेंगे। यह नई सुविधा 16 अप्रैल (वीरवार)से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी, जिसके तहत आमजन ऑनलाइन पोर्टल एससी डॉट सीईएसयूएस डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से अपने परिवार का विवरण भर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल घर-घर जाकर जनगणना शुरू होने से पहले लगभग 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। इस दौरान नागरिक अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर निर्धारित 33 प्रश्नों के उत्तर भर सकते हैं।

पूरी प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है।

एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि जानकारी सफलतापूर्वक जमा करने के बाद नागरिकों को 11 अंकों की एक यूनिक स्व-गणना आईडी प्राप्त होगी। जब जनगणना अधिकारी सत्यापन के लिए घर आएंगे, तो केवल यह आईडी साझा करनी होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा पहली बार लागू की जा रही है, जो पूरी तरह नागरिक हितैषी और तकनीक आधारित है, जिससे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी बनाया जा सके। इस कार्य के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। पोर्टल अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद मकान सूचीकरण का कार्य पारंपरिक तरीके से शुरू होगा। इसके साथ ही जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जनगणना कर्मी घर-घर जाकर साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे, जो सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपडेट होगा।

एसडीएम ने उपमंडल के वासियों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और इस ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि जनगणना प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया जा सके।

सुगनी देवी स्कूल का दसवीं कक्षा का परिणाम रहा शत प्रतिशत

लाडवा, 16 अप्रैल (विजय कौशिक) : सुगनी देवी आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा की प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा ने बताया कि गत दिवस सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा दसवीं का परिणाम घोषित किया गया। जिसमें हमारे स्कूल का परिणाम शत- प्रतिशत रहा । उन्होंने कहा कि कक्षा दसवीं की 74 छात्राओं में से 50 से अधिक छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त कियो जिसमें 10 छात्राएं 90% से ऊपर हैं और 15 छात्राएं 80% से ऊपर हैं छात्रा अलीशा ने 98% अंक लेकर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया । द्वितीय स्थान पर छात्रा अदिति ने 96% अंक और तृतीय स्थान पर नव्या टंडन ने 95% अंक प्राप्त किए पंजाबी में 100 अंक (अलीशा), इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी में 99 अंक (करमन, माही ,अलीशा)इंग्लिश में 98 अंक(अदिति), हिंदी में 98 अंक (अदिति, अलीशा ,नव्या टंडन) साइंस में 97 अंक (अलीशा),सोशल साइंस में 96 अंक (गुरतरण) और मैथ्स में 93 अंक (अदिति) ने लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया` परिणाम घोषित होने पर प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा और मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने अध्यापकों और छात्राओं को मिठाई खिलाकर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रधानाचार्या, सभी अध्यापकों और बच्चों को अच्छे परीक्षा परिणाम की बधाई दी और इस मौके पर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य राजकुमार गर्ग मौजूद रहे। प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा ने कहा कि परीक्षा में विद्यार्थियों के धैर्य और वर्ष भर किए गए परिश्रम की परख होती है। यह सत्य है कि परीक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे अंक पाने की कामना होती है और अच्छे अंक प्राप्त करने से सभी जगह सम्मान होता है।

लाइक पब्लिक स्कूल में रितिका व प्रतीक बने टॉपर

टीम एक्शन इंडिया

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : लाइक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। विद्यालय की मेरिट सूची में रितिका और प्रतीक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान प्राप्त किया।

विषयवार परिणाम में अंग्रेजी में प्रतीक ने 95 व रितिका ने 93 अंक, हिंदी में रितिका ने 93 अंक, जबकि सामाजिक विज्ञान में रितिका ने 96 व प्रतीक ने 94 अंक हासिल किए। अन्य विद्यार्थियों ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्या नेहा देवी व विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सीबीएसई 10वीं में जनता पब्लिक स्कूल का रहा शानदार प्रदर्शन

टीम एक्शन इंडिया

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : जनता पब्लिक स्कूल अलाहर ने सीबीएसई कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में शत-प्रतिशत सफलता हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है।

सभी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के चेयरमैन मुकेश शास्त्री, प्रबंध निदेशक रूबी कम्बोज व प्रधानाचार्या डॉ. कल्पना बजाज ने इस सफलता पर विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम बताया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई।

न्यूज फ्लैश

10वीं के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : स्वराज पब्लिक स्कूल दामला में कक्षा 10वीं (सीबीएसई) का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया। आदर्श ने 97.2 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम, तन्मय ने 96.4 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा हितेन ने 93.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं विषयवार परिणाम में सामाजिक विज्ञान में तन्मय ने 100/100, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आदर्श व अनमोल ने 100/100 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में हितेन व आन्या ने 97/100, हिंदी में तन्मय ने 99/100 तथा गणित में सारिका व एविश ने 91/100 अंक हासिल किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति नागपाल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बुबका स्कूल की दो छात्राओं ने एनएमएमएस परीक्षा में लहराया परचम

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : राजकीय उच्च विद्यालय बुबका की दो छात्राओं पलक और खुशी ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में सफलता हासिल कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल इंचार्ज मलकीत सिंह व स्टाफ ने छात्राओं को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अध्यापिका अनीता, रीतू, महेश, दिव्यांशा, मुकेश, बाला, रानी, मोनिका व जगदीप सहित अन्य उपस्थित रहे और सभी ने छात्राओं को बधाई दी।

बस के नीचे आई बुजुर्ग महिला

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। शहर में आईटीआई चौक पर एक सडक हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बस से उतरते समय अचानक महिला का पैर फिसल गया और वह सडक पर गिर गई, जिससे उसका पैर बस के टायर के नीचे आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घरौंडा की रहने वाली बुजुर्ग महिला हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर करनाल आई थी। आईटीआई चौक पर उतरते समय अचानक एक बच्चा दौडकर बस में चढ? लगा। इस दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। इसी दौरान उसका पैर बस के पहिए के नीचे आ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

10वीं के परीक्षा परिणाम में ग्लोब हेरिटेज स्कूल के 14 छात्रों ने बनाई मेरिट

टीम एक्शन इंडिया

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : ग्लोब हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का कक्षा 10वीं (सीबीएसई) का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। स्कूल की प्रधानाचार्या रीतू सिंगला के अनुसार 28 में से 14 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। निखिल पाल ने 95 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम, अंशिका ने 94 प्रतिशत के साथ द्वितीय, भाविका ने 93 प्रतिशत के साथ तृतीय और रिजुल ने 92 प्रतिशत अंक लेकर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। अन्य कई विद्यार्थियों ने भी मेरिट में स्थान हासिल किया। विषयवार परिणाम में अंग्रेजी व हिंदी सहित अन्य विषयों में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा। स्कूल प्रबंधन व स्टाफ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल की भूमि खत्री 97 फीसदी अंक लेकर बनी स्कूल टॉपर

सफलता

- विद्यार्थियों ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं में हासिल की शानदार सफलता

टीम एक्शन इंडिया

सोनीपत, 16 अप्रैल । पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, कामी रोड के विद्यार्थियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं की परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की है। छात्रा भूमि खत्री ने 97 फीसदी अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। छात्रा सिमरन ने 89.6 फीसदी अंक प्राप्त कर दूसरा व रितिका ने 89 फीसदी अंक लेकर स्कूल में तीसरा स्थान पाया। इनके अलावा तौसीफ ने 88.4 फीसदी, डॉली ने 87.8 फीसदी, अभिनव ने 83.6 फीसदी, हर्षिता ने 83.2 फीसदी, वेदांश त्यागी ने 82.4 फीसदी, दिव्यांश ने 81.6 फीसदी व पुष्प ने 80.6 फीसदी अंक हासिल किया है। पूर्ण मूर्ति कैंपस के चेयरमैन डा.विजयपाल नैन, सचिव गौतम नैन, स्कूल की प्रधानाचार्या हिमानी दहिया व उप प्रधानाचार्य वरुण ने छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

डा.विजयपाल नैन ने बताया कि विद्यालय का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यालय की प्राचार्या व टीचिंग स्टाफ को दिया, जिनकी देख-रेख में विद्यार्थियों ने यह सफलता हासिल की है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ग्यारहवीं कक्षा में विषयों को चयन में बेहद सावधानी बरते। यह फैसला बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही आपके भविष्य की नींव रखता है। स्कूल की प्रधानाचार्या हिमानी दहिया ने कहा कि विषयों के चयन का फैसला छात्रों को बहुत सोच-समझकर ही लेना चाहिए क्योंकि इससे कई मायनों में करियर की दिशा तय हो जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है सामाजिक दबाव या प्रभाव से दूर रहना और अपनी रुचियों को पहचानना। जो आपको पसंद हो, उसे चुनें। यह भी ध्यान रखें कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई रास्ते होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज या दोस्तों के दबाव में आकर फैसला न लें।

इस मौके पर स्कूल की कोऑर्डिनेटर मीनाक्षी, अध्यापिका शीतल, विनम, रितु, नीलम, निशा, निशु सहित सभी स्टाफ सदस्यों ने दसवीं की परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी।

सीवरेज व पेयजल जैसी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित करें निपटान: एडीसी

टीम एक्शन इंडिया

भिवानी, 16 अप्रैल। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। समाधान शिविर में एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर निर्धारित समय सीमा में उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सीवरेज, पेयजल, अतिक्रमण व अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निपटान के निर्देश दिए। समाधान शिविर में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला ने भी पीपीपी से संबंधित समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एडीसी के समक्ष पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने ढाणा लाढ?पुर स्थित संत कबीर आश्रम की साफ-सफाई व मरम्मत करवाने तथा ढ़ाणा नरसान क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से अधूरे पड़े राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा करवाने की समस्या रखी। गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार ने शहर के हांसी गेट, घंटाघर और बिचला बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने, पटेल नगर निवासी जगदीश चंद्र ने अपने मकान के नीचे से सीवरेज व पानी की लाइन गुजरने की जांच करवाने, हवासिंह ने तोशाम बाईपास पर जमीन की अधूरी जमाबंदी पूरा करवाने की समस्या रखी।

गैर-सरकारी सदस्य केके. ग्रोवर ने चौधरी बंसीलाल राजकीय अस्पताल के सामने अवैध रूप से लगी रेहडि?ों को हटवाने, डीसी कॉलोनी निवासी बलवान सिंह ने अपनी माता के नाम प्लॉट का इंतकाल करवाने, रेवाड़ी खेड़ा निवासी तारा ने गली में अवैध अतिक्रमण हटाने, बुसान निवासी कमला ने प्लॉट से कब्जा हटवाने, तालू निवासी विनोद ने आम रास्ते में खड़े बिजली के पोल हटवाने तथा खेतों में जलभराव से नुकसान पर मुआवजा दिलवाने, गुजरानी वासियों ने तालाब की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने की शिकायत रखी।

एडीसी के समक्ष डाबर कॉलोनी निवासी पुलकित तंवर ने गली नंबर-25 में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने, उषा ने विवाह शुगन योजना का लाभ दिलवाने, गैर-सरकारी सदस्य अनिल सोलंकी ने नेशनल हाईवे से जुड़े हनुमान गेट, हनुमान चौक व हनुमान ढाणी क्षेत्र में डाली गई मिट्टी हटवाने व पेयजल लाइन की लीकेज ठीक करवाने, कविता ने बच्चों की स्कूल में दाखिला व फीस माफ करवाने, पार्षद संदीप ने सेक्टर-13 स्थित नगर परिषद कम्युनिटी सेंटर में चौकीदार व सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त करवाने, सेक्टर-13 की मार्केट में सीवर की सफाई व स्ट्रॉग वाटर ड्रेनेज का अलग कनेक्शन करवाने, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में स्टॉग वाटर ड्रेनेज की सफाई करवाने, खराब पड़े स्ट्रॉग वाटर बूस्टर व जेनरेटर को जल्द ठीक करवाने की समस्या रखी। लगाने की अपील की।

एसजीएमपीएस लाडवा के विद्यार्थियों ने किया कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन

टीम एक्शन इंडिया

लाडवा, 16 अप्रैल (विजय कौशिक) संजय गांधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, धनोरा-लाडवा के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने मार्च 2026 में आयोजित बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रधान पवन गर्ग ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी को बधाई दी और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। स्कूल सचिव रविंद्र बंसल, सह-सचिव नरेंद्र सिंघल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गिल, प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा

और शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय का परिणाम 100% रहा है और कुल 44 छात्र मेरिट सूची में शामिल हैं। स्कूल की मेधावी छात्रा छवि ने कुल 98% अंक प्राप्त कर के प्रथम स्थान, धृति ने कुल 94.4% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान और नीरव एवं निपुण ने कुल 94.2% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने अटूट विश्वास और समर्थन के लिए प्रबंधन और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सत्र के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा दिखाए गए लगन, परिश्रम और अनुशासन की सराहना की।

न्यूज फ्लैश

दलबीर सिंह ने संभाला केयू के गणित विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर सिंह मलिक
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ के आदेशानुसार गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर श्री दलबीर सिंह ने गुरुवार को गणित विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार विधिवत रूप से संभाला। यह जानकारी लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने दी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही श्री दलबीर सिंह एकेडमिक काउंसिल तथा फैकल्टी ऑफ साइंसेज के सदस्य होंगे तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन भी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री दलबीर सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन पर जताया गया विश्वास उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वे गणित विभाग की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध गतिविधियों तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। इस अवसर पर डॉ. अनुपम खन्ना, डॉ. सुरेन्द्र सिंह, डॉ. विकास पोपली, श्रीमती सुमित्रा देवी सहित विभाग के शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे।

गांव सिंबलगढ़ व आसपास के गांवों में अवैध खनन, पंचायत मंत्री से की शिकायत

समालखा (संजय नरवाल) आज पंचायत एवं खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार जी को गांव राक्सेडा मे,रेत परिवहन की आड़ लेकर, यमुना नदी में चल रहे अवैध रेत के खनन को रोकने के लिए ,कई गांव के ग्रामीण ,ग्राम सिंबलगढ़ सरपंच श्री सतीश कुमार जी के नेतृत्व में खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार जी के समक्ष यमुना नदी में चल रही , अवैध रेत की खान को रोकने की अपील की और कहा कि अगर यह रेत की खान नहीं रुकेगी, तो कई गांव के जमीदारों की जमीन, गांव हथवाला, गांव कारकोलीगढ़, गांव रक्सेड़ा, गांव सिंबलगढ़ गांव बुधनपुर ,आदि गांव के किसानों की जमीन यमुना नदी में कट जाएगी और किसानों को सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएगा।

अजमत अली ने चार बच्चों को पाकिस्तान से भारत वापस लाने में मदद की लगाई गुहार

अजमत अली की पत्नी नाहिद 2017 में चारो बच्चों को लेकर चली गई थी पाकिस्तान

मदद की गुहार

पत्नी में हमारे चार बच्चों को साथ लेकर वहां पर परिवार वाले से मिलने का नाम लेकर पाकिस्तान चली गई

टीम एक्शन इंडिया
पानीपत, 15 अप्रैल (बिजेंद्र सिंह)। यूपी के मुरादाबाद के व्यक्ति अजमत अली ने बुधवार को यहां एडवोकेट मोमिन मलिक के चैंबर में पत्रकार वार्ता में बताया कि उसकी पत्नी वर्ष 2017 में हमारे चार बच्चों को साथ लेकर वहां पर परिवार वाले से मिलने का नाम लेकर पाकिस्तान चली गई। वह अब अपने चारो बच्चों को वापस लाने को लेकर भटक रहा है और उसने इसके लिये भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार व मानवाधिकार आयोग को गुहार लगाई है। वहीं अजमत अली ने यहां पर एडवोकेट मोमिन मलिक से मिलकर उसके चार बच्चों को वापस भारत लाने के लिये मदद करने की अपील की है।
इस मौके पर एडवोकेट मोमिन मलिक ने बताया कि करीब 30 साल पहले अजमत अली अपनी रिश्तेदारी में पाकिस्तान गया था और वहां पर इसकी शादी नाहिद से कर दी गई। अजमत अपनी पत्नी नाहिद को लेकर मुरादाबाद आ गया और मुरादाबाद में ही रह रहा था। अजमत अली व नाहिद के चार बच्चे हुए पर इसकी पत्नी चारो बच्चों को लेकर 2017 में पाकिस्तान चली गई।
चारो बच्चों के भारतीय पासपोर्ट थे और पाकिस्तान एंबेसी से वीजा लेकर गये थे। अजमत अली अपने चारो बच्चों को लेने के लिये पाक एंबेसी से वर्ष 2022 में तीन माह का वीजा लेकर पाकिस्तान गया था पर इसको इसके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। इसने तीन माह का वीजा बढाने का वहां पर आवदेन दिया पर वीजा बढाया नहीं गया।
इसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया और करीब 17 माह लाहौर जेल में रहा और फिर उसके बाद भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इस मौके पर अजमत अली ने बताया कि उसकी भारत सरकार से मांग है कि उसके चारों बच्चों को पाकिस्तान से वास भारत लेकर आने में उसकी मदद की जाये। अजमत ने कहा कि उसकी पत्नी नाहिद ने वहां पर तलाक होने की बात कही थी पर हमारा तलाक नहीं हुआ है। अजमत की मांग है कि उसकी पत्नी बेशक पाकिस्तान में ही रहे पर मेरे चारो बच्चों को भारत लाने में मदद की जाये।
वहीं मोमिन मलिक एडवोकेट ने कहा कि वह अजमत अली के चारो बच्चों को कानूनी तरीके से पाकिस्तान से वापस भारत लाने का पूरा प्रयास करेगे और इसके लिये अजमत अली की एक वकील के रूप मे पैरवी करेंगे।

हिमगिरी पब्लिक स्कूल का रहा शानदार परीक्षा परिणाम

समालखा (संजय नरवाल) हिमगिरी पब्लिक स्कूल समालखा के विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार कुल 63 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी सफल रहे, जिससे विद्यालय का परिणाम अत्यंत सराहनीय रहा। विशेष रूप से 21 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया।प्रथम स्थान पर आदर्श झा ने 94.4■ अंक प्राप्त किए।द्वितीय स्थान पर नैंसी ने 91.4■ अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर लक्ष्य ने 90.2■ अंक प्राप्त कर अपना स्थान बनाया।नैतिक, दीपिका, अदिति, मानसी, मानसी कंडेरा, सूर्यांश, ऋषि राज, अर्पिता, लवली, साक्षी, वीना, चाहत, इशिका, अनीता, तनिश, स्नेह लता, निखिल गुप्ता इन सभी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। इस अवसर पर विद्यालय की मैनेजर विजयलक्ष्मी राठी, चेयरमैन राजबीर राठी (सेवानिवृत्त उप जिला शिक्षा अधिकारी), प्रधानाचार्य प्रमोद राठी, उप-प्रधानाचार्या रितु लठवाल, प्रशासनिक अधिकारी रामनिवास, ज्योति कोचर, शालू कालडा,किरण समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। साथ ही टॉपर्स के अभिभावक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की। यह दृश्य आपसी प्रेम, सहयोग और सफलता के उत्सव का प्रतीक रहा, जिसने सभी को आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग को दिया गया। इसी के साथ चेयरमैन राजबीर जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि इस सत्र से संघ लोक सेवा आयोग जैसी ऊँच नौकरियों की तैयारी शुरू करवा दी गई है इस खबर को सुनकर बच्चों अभिभावकों और अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ उठी।

सीबीएसई 10वीं में जनता पब्लिक स्कूल का रहा शानदार प्रदर्शन

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : जनता पब्लिक स्कूल अलाहर ने सीबीएसई कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में शत-प्रतिशत सफलता हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सभी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के चेयरमैन मुकेश शास्त्री, प्रबंध निदेशक रूबी कम्बोज व प्रधानाचार्या डॉ. कल्पना बजाज ने इस सफलता पर विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम बताया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई।

इंद्री अनाज मंडी में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म, सर्वसम्मति से सुलझा विवाद

इंद्री 16 अप्रैल (मैनपाल कश्यप) इंद्री की अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर बुधवार शाम प्रशासन और ट्रांसपोर्टरों के बीच उत्पन्न हुआ विवाद गुरुवार को आपसी सहमति से सुलझ गया। विवाद के चलते ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे मंडी में गेहूं उठान का कार्य प्रभावित हो गया था। हालांकि प्रशासन और ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच हुई बैठक के बाद अब मंडी में गेहूं उठान का कार्य फिर से सुचारु रूप से शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम मंडी में गेहूं उठान के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था नहीं होने पर ट्रांसपोर्टरों और एसडीएम इंद्री के बीच कहासुनी हो गई थी। मामला बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट मालिकों ने काम बंद कर हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग रुक गई और किसानों व आढ़तियों की चिंता बढ़ गई। गुरुवार को एसडीएम रमन गुप्ता, डीएसपी सतीश गौतम, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आढ़ती प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें सभी पक्षों ने मिलकर विवाद का समाधान निकाल लिया। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सुमेर चंद कंबोज ने बताया कि मंडी में गाड़ियों की संख्या को लेकर गलतफहमी पैदा हुई थी। ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि मंडी में 70 गाड़ियों की जरूरत है, जबकि मौके पर केवल 45 से 50 गाड़ियां ही गेहूं उठान में लगी थीं। बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और मामला शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान अशोक खुराना ने बताया कि प्रशासन और ठेकेदार के बीच कुछ मतभेद थे, जिन्हें सर्वसम्मति से दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमों के चलते शुरूआत में कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब मंडी में गेहूं उठान पूरी तरह सामान्य हो गया है। विवाद सुलझने के बाद मंडी में किसानों और व्यापारियों ने राहत महसूस की है और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने का भरोसा दिया है। डीएसपी सतीश गौतम ने सभी ट्रांसपोर्टरों के बीच में बैठक सर्वसमति से मामले को शांत करवा दिया गया है मंडी में सभी ट्रांसपोर्ट अपने कार्य पर पर लोट गए और उन्हें अपना काम शुरू कर दिया है।

सर्व समाज सभा की बैठक में बरसाती नालों व सीवरेज की सफाई की मांग

टीम एक्शन इंडिया
डॉ नैब सिंह मंडेर

मांग

सभा सदस्यों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुधार करवाया जाए

रतिया,16 अप्रैल : सर्व समाज सभा रतिया की विशेष बैठक बाबा नामदेव धर्मशाला में प्रधान सतपाल जिंदल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महासचिव डॉ नैब सिंह मंडेर ने स्वागत करते हुए बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। प्रेस सचिव हैप्पी सिंह सेठी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सभा की बैठक में मुख्य रूप से बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सीवरेज एवं बरसाती नालो की सफाई करवाए जाने की मांग की गई और इस संबंध में सर्व समाज सभा का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही एस डी एम से मिलकर बरसाती जल की निकासी बारे मांग करेगा। बैठक में प्रस्तुत मांग कि शहर के विभिन्न वार्डो में अलग अलग मौहलों के नाम पर चर्चा करते हुए सभा सदस्यों ने बैठक में मुद्दा उठाया कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र की लोकेशन आनलाइन सिस्टम में दिखनी चाहिए और काफी लंबे समय से हम देखते आ रहे कि जिस क्षेत्र में हम रहते ही नही मुहल्ला लोकेशन किसी और जगह की उठाई जा रही है। सभा सदस्यों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुधार करवाया जाए ताकि किसी भी कार्य में मकान, घर आदि की लोकेशन उठानी हो तो कोई समस्या न आए। इस मौके पर महासचिव डा नैब सिंह मंडेर,उपाध्यक्ष नरेंद्र ग्रोवर, कोषाध्यक्ष शेर सिंह भुल्लर, बलिंद्र शर्मा, सहसचिव रणधीर सिंह मोलिया, डॉ सुनील इंदौरा, राजेंद्र मोंगा, धर्मपाल शर्मा,विनोद जिंदल,हरप्रीत सिंह भुल्लर सहित मौजूद रहे।

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया की ली समीक्षा

इंद्री 16 अप्रैल(मैनपाल कश्यप) उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी एसडीएम और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम को मंडियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी गई फसल का मंडियों से समय पर उठान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद और उठान की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि मंडियों में सुचारू व्यवस्था बनी रहे। इस मौके पर एडीसी डॉ राहुल रईया, एसडीएम करनाल देवेंद्र शर्मा व वीसी के माध्यम से सभी संबंधित एसडीएम, डीएफएससी व खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पंचायती भूमि से पेड़ काटने के आरोप में मामला दर्ज

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : ग्राम पंचायत घिलौर की पंचायती भूमि से अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में रादौर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिमरन ने बताया कि गांव घिलौर के खसरा नंबर 123 की पंचायती भूमि पर महेंद्र सिंह द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा किया हुआ है। आरोप है कि 7 अप्रैल को उसकी पत्नी प्रकाशो देवी और ठेकेदार सतीश कुमार ने उक्त भूमि पर खड़े चार पेड़ों को काटकर बेच दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कृतीका मिगलानी ने 95.6 प्रतिशत अंकों के साथ सेंट थोमस कानवेंट स्कूल में किया टॉप

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर सिंह मलिक
कुरुक्षेत्र : सेंट थोमस कानवेंट स्कूल कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों का सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में शत प्रतिशत रिजल्ट हासिल किया है। छात्रा कृतीका मिगलानी ने 95.6 प्रतिशत अंकों के साथ स्कूल में टॉप किया। इस परिणाम पर प्रबंधक कमेटी एमडी अंजली, डिप्टी एमडी कार्तिके व प्राचार्या रजनी ने 10वीं के बेहतर परिणाम आने पर विद्यार्थियों और स्टाफ को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा में 55 विद्यार्थियों ने सीबीएसई की परीक्षा में हिस्सा लिया था। स्कूल का परिणाम शत प्रतिशत रहा। स्कूल की छात्रा कृतीका मिगलानी ने 95.6 प्रतिशत अंकों के साथ स्कूल में प्रथम, जसमीन ने 94.4 अंकों के साथ दूसरे और अरव सैनी ने 90.6 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। स्कूल के 27 विद्यार्थियों ने 75 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए।
उन्होंने कहा कि स्कूल स्टाफ की लगन और बच्चों के सहयोग से कड़ी मेहनत की है। जिसके बदोलत स्कूल ने बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। इससे पहले भी स्कूल का परिणाम बेहतर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो आगे भी लगन और मेहनत से पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। विद्यार्थी की सफलता से माता-पिता, शिक्षक और स्कूल का नाम रोशन होता है।

लाइक पब्लिक स्कूल में रितिका व प्रतीक बने टॉपर

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : लाइक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। विद्यालय की मेरिट सूची में रितिका और प्रतीक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान प्राप्त किया। विषयवार परिणाम में अंग्रेजी में प्रतीक ने 95 व रितिका ने 93 अंक, हिंदी में रितिका ने 93 अंक, जबकि सामाजिक विज्ञान में रितिका ने 96 व प्रतीक ने 94 अंक हासिल किए। अन्य विद्यार्थियों ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्या नेहा देवी व विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

10वीं के परीक्षा परिणाम में ग्लोब हेरिटेज स्कूल के 14 छात्रों ने बनाई मेरिट

रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : ग्लोब हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का कक्षा 10वीं (सीबीएसई) का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। स्कूल की प्रधानाचार्या रीतू सिंगला के अनुसार 28 में से 14 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया।\
निखिल पाल ने 95 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम, अंशिका ने 94 प्रतिशत के साथ द्वितीय, भाविका ने 93 प्रतिशत के साथ तृतीय और रिजुल ने 92 प्रतिशत अंक लेकर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।
अन्य कई विद्यार्थियों ने भी मेरिट में स्थान हासिल किया। विषयवार परिणाम में अंग्रेजी व हिंदी सहित अन्य विषयों में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा। स्कूल प्रबंधन व स्टाफ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रिया 99 फीसदी अंक लेकर बनी ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल की टॉपर

टीम एक्शन इंडिया
सोनीपत। ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल (जी-3) के विद्यार्थियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं की परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की है। परीक्षा परिणाम आशा के अनुरूप आने पर परीक्षार्थियों के चेहरे खिल गए। छात्रा प्रिया ने 99 फीसदी अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं छात्र गर्वित ने 98.4 फीसदी अंक हासिल कर दूसरा व छात्रा हर्षिता ने 97 फीसदी अंक के साथ स्कूल में तीसरा स्थान पाया। साथ ही किरन ने 96 फीसदी अंक लेकर चौथा, अनीश ने 95.8 फीसदी अंक के साथ पांचवां और अभय ने 95.6 फीसदी अंक हासिल कर स्कूल में छठा स्थान हासिल किया। इसके अलावा रिशु ने 94.2 फीसदी, सेजल ने 93.8 फीसदी, नेहल ने 93.6 फीसदी, हर्षिल ने 92.4 फीसदी, पूर्ति ने 92.2 फीसदी, श्रव्या वाही ने 92 फीसदी, मंदीप ने 91.8 फीसदी व प्रिया सांगवान ने 90.6 फीसदी अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
शानदार परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र-छात्राओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन सुधीर जैन, डायरेक्टर ध्रुव जैन, प्राचार्या गीता चोपड़ा व उप प्राचार्या रूना दास ने छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
सुधीर जैन ने बताया कि स्कूल का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। स्कूल के 14 विद्यार्थियों ने 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यालय की प्राचार्या व टीचिंग स्टाफ को दिया, जिनकी देख-रेख में छात्र- छात्राओं ने यह सफलता हासिल किया। प्राचार्या गीता चोपड़ा ने बताया कि स्कूल टॉपर प्रिया ने आईटी में 100, गणित में 99, सोशल साइंस में 99, अंग्रेजी में 99, साइंस में 98 व हिंदी में 97 अंक हासिल किए। द्वितीय टॉपर गर्वित ने सोशल साइंस में 100 अंक व तृतीय टॉपर हर्षिता ने आईटी में 100 अंक हासिल कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया ।

न्यूज फ्लैश

नगर निगम सोनीपत के आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी

सोनीपत, 16 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि नगर निगम सोनीपत के मेयर व निगम पार्षद चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा ने अधिसूचना जारी की हैं। उन्होंने बताया कि मेयर व निगम पार्षद के लिए 10 मई को सुबह 08 बजे से 06 बजे तक मतदान आयोजित किया जाएगा और 13 मई को मतगणना प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मेयर व निगम पार्षद के लिए उम्मीदवार 21 से 25 अप्रैल तक अपने नामांकन दाखिल करवा सकेंगे।

जिला निर्वाचन आयोग ने नगर निगम सोनीपत के आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए हरियाणा नगर निगम, निर्वाचन अधिनियम 1994 के नियम 21(3) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेयर व निगम पार्षद चुनाव के लिए रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने संशोधित आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा को मेयर तथा एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र को पार्षद चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

नगर निगम मेयर चुनाव के लिए भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासक) सुरेन्द्र सिंह को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम मेयर के लिए उम्मीदवार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा सकेंगे। इसी प्रकार वार्ड 01 से 07 तक निगम पार्षद का चुनाव लडने वाले उम्मीदवार न्यायालय जिला राजस्व अधिकारी सोनीपत, वार्ड 08 से 14 तक न्यायालय उप-मंड़ल अधिकारी (ना.) सोनीपत, व वार्ड 15 से 22 तक बीडीपीओ सोनीपत कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दर्ज करवा सकेंगे।

वार्ड 01 से 07 के निगम पार्षद चुनाव के लिए शुगर मील सोनीपत की एमडी डॉ० अनमोल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी 1 व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मनीष मलिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी 2, वार्ड 08 से 14 के लिए एसडीएम खरखौदा अमित को सहायक रिटर्निंग अधिकारी 1 व नायब तहसीलदार राई अभिनव को सहायक रिटर्निंग अधिकारी 2, वार्ड 15 से 22 के लिए शुगर मील गोहाना की एमडी अंकिता वर्मा का सहायक रिटर्निंग अधिकारी 1 व खण्ड़ विकास एवं पंचायत अधिकारी, गन्नौर राजेश टिवाना को सहायक रिटर्निंग अधिकारी 2 नियुक्त किया गया है।

अवैध हथियार सहित आरोपी काबू

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। सीआईए 2 टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित मामले में प्रदीप पुत्र सुभाष निवासी बाल्मीकि बस्ती निसिंग को आवर्धन नहर से काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्तौल .315 बोर बरामद की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शौकिया तौर पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से खरीदकर लाया था। पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान संदेह के आधार पर आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से उक्त अवैध हथियार बरामद किए गया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना निसिंग में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी से गहन पूछताछ कर अवैध हथियार के इस नेटवर्क से संबंधित सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ के लिए अग्रिम अनुसंधान जारी है।

विश्व हिमोफिलिया दिवस पर हुआ कैंप का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सतपाल सिंह के मार्गदर्शन में आयुष ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्राम कालरो में विश्व हिमोफिलिया दिवस के अवसर पर कैंप का आयोजन पंचायत भवन में किया गया, जिसमें डॉ. धर्मवीर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी तथा डा. शीतल ने हिमोफिलिया रोग की जानकारी तथा रोगियों की निशुल्क जांच की।

युक्त धारा के उपयोग से काम में आएगी पारदर्शिता : डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान

शुभारंभ

- जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली ग्राम पंचायतों के विकास में एक नई क्रांति लेकर आएगी

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। युक्तधारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की सटीक योजना बनाना, उनकी वास्तविक समय में निगरानी करना और संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना संभव होगा। इससे न केवल कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आएगी। यह बात हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कही। वे संस्थान में तीन दिवसीय वीबी-जी राम जी के अंतर्गत युक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायतों की जीआईएस आधारित निगरानी विषय पर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। डॉ चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

कार्यक्रम समन्वयक संस्थान के संकाय सदस्य डॉ. कमलदीप सांगवान ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के कार्यों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है।

निदेशक डॉ.वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जीआईएस आधारित निगरानी से ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, यही डिजिटल ग्रामीण विकास की दिशा है। उन्होंने कहा कि जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में एक नई क्रांति लेकर आएगी।

डॉ. चौहान ने कहा कि प्रतिभागियों को जीआईएस तकनीक और युक्तधारा के व्यावहारिक उपयोग में दक्ष बनाना है, ताकि वे अपने.अपने क्षेत्रों में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही योजना निर्माण, संसाधनों का संतुलित उपयोग और कार्यों की निरंतर निगरानी ही विकास को गति देती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें नवीन तकनीकों के प्रति जागरूक बनाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि वे एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस देशव्यापी अभियान के लिए हरियाणा को पहला राज्य चुना।

जिला में हुई 86 पैक्स कंप्यूटरीकृत : राहुल रईया

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिला की प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण को लेकर एक बैठक जिला सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त डा. राहुल रईया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिला में 98 पैक्स हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 86 को ई-पैक्स में परिवर्तित किया जा चुका है। इनमें से 45 पैक्स में अब आय-व्यय के ब्यौरे का विवरण प्रतिदिन दर्ज कर उसका मिलान भी साथ-साथ किया जाता है। बाकी 12 के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने अगले 15 दिनों में बाकी पैक्स में भी डायनेमिक डे-एंड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस बारे में पैक्स को सभी आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में एडीसी ने स्टाफ की स्थिति, पदोन्नति प्रक्रिया, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने, पैक्स की आर्थिक स्थिति आदि में बारे में भी जानकारी ली।

पंचायती भूमि से पेड़ काटने के आरोप में मामला दर्ज

टीम एक्शन इंडिया
रादौर, 16 अप्रैल (कुलदीप सैनी) : ग्राम पंचायत घिलौर की पंचायती भूमि से अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में रादौर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिमरन ने बताया कि गांव घिलौर के खसरा नंबर 123 की पंचायती भूमि पर महेंद्र सिंह द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा किया हुआ है। आरोप है कि 7 अप्रैल को उसकी पत्नी प्रकाशो देवी और ठेकेदार सतीश कुमार ने उक्त भूमि पर खड़े चार पेड़ों को काटकर बेच दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

उपायुक्त ने गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया की ली समीक्षा बैठक

समीक्षा

- उपायुक्त ने कहा कि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में असुविधा नहीं होनी चाहिए

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी एसडीएम और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम को मंडियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद व उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उपायुक्त ने कहा कि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी गई फसल का मंडियों से समय पर उठान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि खरीद और उठान की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें, ताकि मंडियों में सुचारू व्यवस्था बनी रहे। इस मौके पर एडीसी डॉ राहुल रईया, एसडीएम करनाल देवेंद्र शर्मा व वीसी के माध्यम से सभी संबंधित एसडीएम, डीएफएससी व खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। शहर के बसंत विहार क्षेत्र में बीती देर रात एक व्यक्ति का शव शराब के ठेके के सामने पड़ा मिला। घटना का पता चलते ही आसपास के लोगों में हडकंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय सतीश कुमार के रूप में हुई है। वह अविवाहित था और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। सतीश कुमार बसंत विहार में किराए के मकान में अकेला रहता था। बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था और अक्सर ठेके के आसपास देखा जाता था। पुलिस को शव के पास से एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें सेव नंबरों के आधार पर संपर्क किया गया। इसके बाद ही मृतक की पहचान हो सकी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। इसके बाद शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया।पुलिस के अनुसार आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सदर थाना के थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

गांव चलो-बस्ती चलो जन सेवाओं का महत्वपूर्ण अभियान : डा. अशोक कुमार

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। गांव चलो-बस्ती चलो अभियान के तहत नगर निगम के वार्ड 12 के चार चमन इलाके एवं बूथ नंबर 33, 34, 35 में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कर्ण मंडल उपाध्यक्ष आकाश अरोड़ा एवं शक्ति केंद्र प्रमुख सतीश कश्यप की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर मुख्य तौर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं शक्ति केंद्र पालक डा.अशोक कुमार के अलावा शक्ति केंद्र सह प्रमुख नंद लाल, बूथ अध्यक्ष पुष्पिंदर माथुर, ओम प्रकाश, रविन्द्र कश्यप, अशोक कुमार वर्मा एवं अनिल पाहवा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य आवश्यकताओं को क्षेत्र के घर-घर तक पहुंचाने हेतु विचार-विमर्श कर समीक्षा की गई। बैठक में उत्साह से भरपूर समर्पित कार्यकर्ताओं ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा का संकल्प लिया।

बैठक में गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए ड्यूटियां निर्धारित की गई।

जिला मीडिया प्रभारी डा. अशोक कुमार ने बताया कि पार्टी द्वारा चलाया जा रहा गांव चलो-बस्ती चलो अभियान प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क और जनसेवा का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य गांव-गांव और बस्ती-बस्ती तक पहुंचकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस अभियान में पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रत्येक मंडल, बूथ एवं शक्ति केंद्र स्तर पर युवाओं की टीम बनाकर घर-घर संपर्क किया जा रहा है। कार्यकर्ता जनता को सरकार की उपलब्धियों से अवगत करा रहे हैं और उनके सुझाव भी प्राप्त कर रहे हैं।

आगामी एक मई से तीस मई तक मकानों का सूचीकरण एवं गणना की जाएगी: राजीव जैन

टीम एक्शन इंडिया

सोनीपत, 16 अप्रैल। नगर निगम के निवर्तमान मेयर राजीव जैन ने हरियाणा राज्य में स्व-गणना अभियान के शुरू होने के पहले ही दिन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करके सभी से दिनांक 16 से 30 अप्रैल के बीच अपनी जानकारी दर्ज करने की अपील की। राजीव जैन ने कहा कि आपकी सहभागिता राज्य की बेहतर योजना निर्माण, सेवा वितरण में सुधार तथा समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि

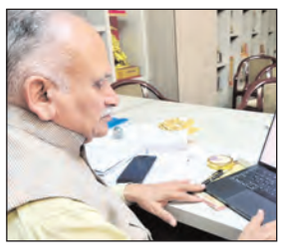

उनके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी गोपनीय एवं सुरक्षित रखी जाएगी। इन आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक कहीं से भी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा हरियाणा के सभी जिलों में उपलब्ध है, मोबाइल फोन, टेबलेट एवं कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग, एक यूनिक आई डी प्रदान की जाएगी। प्रगणक केवल जानकारी का सत्यापन करेंगे।

राजीव जैन ने बताया कि आगामी एक मई से तीस मई तक मकानों का सूचीकरण एवं गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 वर्षों के बाद दोबारा जनगणना हो रही है इसी के आधार पर लोकसभा, विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा तथा स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या तय होनी है।

2 किलो 80 ग्राम गांजा फूल पत्ती सहित आरोपी काबू

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा
करनाल।

सीआईए-2 की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चुना कुमार झा पुत्र पशुपति नाथ झा, निवासी राहटमीना, हलदरहाट, जिला बिहार, को तरावड़ी करनाल से काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 किलो 80 ग्राम गांजा फूल पत्ती नशीला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना तरावड़ी में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी काबू

टीम एक्शन इंडिया
कमल मिड्ढा

करनाल। जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना राम नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष पुत्र प्रमोद वासी गुरुनानकपुरा कॉलोनी, पिंगली चौक करनाल तथा हिमांशु पुत्र ईश्वर चंद वासी गुरुनानकपुरा कॉलोनी, पिंगली चौक करनाल के रूप में हुई है। एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज ने

बताया कि टीम द्वारा गश्त के दौरान दोनों आरोपियों को काबू किया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 5 किलो 64 ग्राम गांजा फूल-पत्ती तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जल्दी अमीर बनने और अपने शौक पूरे करने के लिए गांजा बेचने का कार्य करते थे, जिनके खिलाफ एनडीपीएस की संबंधित धाराओं के तहत थाना राम नगर, जिला करनाल में दर्ज किया गया। टीम द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया, जहां से उनका दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया।

रिमांड के दौरान आरोपियांन से गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि इस मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों व सप्लाई चैन का खुलासा किया जा सके। जिला पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशा तस्करी जैसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

स्वच्छता को लेकर वार्ड कमेटियां प्रशासन और जनता के बीच की मजबूत कड़ी : मुख्यमंत्री नायब सैनी

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस

करनाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है और इसे जन आंदोलन बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से हाल ही में प्रदेश में स्थापित नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका में वार्ड वाईज करीब 1520 कमेटियों का गठन किया जा चुका है, शेष स्थानीय निकायों के वार्डों में भी गठन हो जाएगा। उन्होंने वार्ड वाईज गठित समिति के सदस्यों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ें और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। सभी सदस्य अपनी.अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, इससे जहां क्षेत्र स्वच्छ बनेगा, वहीं सदस्यों को भी एक अलग पहचान भी मिलेगी और सम्मान हासिल होगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1 मई से आगामी 15 मई तक विशेष स्वच्छता अभियान शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलाया जाएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल तौर पर जुडकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में वार्ड वाईज गठित कमेटी के सदस्यों, नगर निगम महापौरों, नगर परिषद व नगर

पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व नगर पार्षदों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक ऐसा विषय है, अगर उस पर पूर्ण रूप से ध्यान न दिया जाए तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव समाज पर दिखाई देता है। इसलिए सभी कमेटी सदस्य मेरा वार्ड स्वच्छ वार्ड बनाने के लिए मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि वार्ड वाईज कमेटियां प्रशासन और जनता के बीच में एक मजबूत सेतु का काम करें। अगर जनता की कोई शिकायत स्वच्छता को लेकर समिति के सदस्यों की ओर से जिला अधिकारियों के पास पहुंचती है, तो उसका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए।

इसके अलावा राज्य स्तर पर भी शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए तथा समिति की ओर से वार्ड वाईज आए सुझाव पर गंभीरता से विचार करें और सरकार के संज्ञान में लाया जाए, ताकि लोगों की मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ड वाईज समिति के अध्यक्ष के रूप में वार्ड का नगर पार्षद कार्य करेगा और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय का अधिकारी-कर्मचारी सचिव के रूप में समिति के सदस्यों का सहयोग करेगा।

उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य लोगों में जागृति लाएं कि वे कूड़े-कचरे को इधर-उधर न फैंकें, बल्कि डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ी में ही कचरा डाला जाए। इसके अलावा सूखे व गीले कचरे को भी अलग-अलग डस्टबिनों में डालने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए। इससे आम जनता की सोच में बदलाव आएगा।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे कूड़े-कचरे के निपटान के लिए जिन एजेंसियों के पास टेंडर हैं, वे उनके वाहनों, कर्मचारियों की संख्या की उपलब्धता पर भी नजर रखें। अगर कहीं पर भी लापरवाही नजर आती है तो उनके खिलाफ जुमार्ना व प्रशासनिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य स्वच्छता के साथ-साथ आम जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्ड कमेटियों के गठन का उद्देश्य लोगों की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने के निर्णय में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वार्ड कमेटी के सदस्यों की क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करना है, वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता प्रदान करना और स्वच्छता कार्यों का पर्यवेक्षण करना, वार्ड में विभिन्न समूहों के लोगों के बीच सद्भाव और एकता को प्रोत्साहित करना, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लाभार्थियों की पहचान के लिए सहायता प्रदान करना, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलकूद को प्रोत्साहित करना, नगर निगम को देय करों, शुल्कों और अन्य राशियों की समय पर वसूली में सहायता करना और सभी राजस्व स्रोतों की इष्टतम वसूली सुनिश्चित करना, पार्कों, खेल के मैदानों, सडकों और स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव को सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है।

ACTION INDIA

एक्शन इंडिया

RKB GROUP Rakesh Bhardwaj Group

Front Page - 2

एक्शन इंडिया ▸ देहरादून ▸ 17 अप्रैल 2026 ▸ पृष्ठ 08 ▸ आरएनआईः UTTHIN / 2009 / 31653

समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग व सुविधाओं से बना सुरक्षा का बेहतर माहौलः योगी

○ वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

टीम एक्शन इंडिया

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का मॉडल खड़ा हुआ। उन्होंने बताया कि बीते नौ वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वर्कशाप बनाए गए हैं। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवन का लोकार्पण करने के बाद भ्रमण और निरीक्षण कर भवन में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। पर, हम उसका एक ही पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। योगी ने कहा कि पहले भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे।

सुरक्षा का माहौल

□ बीते नौ वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है : सीएम

नौ वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती

वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 के पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय मे तीन हजार से अधिक नहीं थी। वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है। योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो या पीएसी वाहिनी हो, कहीं पर पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी आवासीय सुविधा और अच्छे बैरक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहकर जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करता था। कई बार शिकायत आती थी कि पुलिस वाले ने घर पर कब्जा कर लिया है। वह कब्जा नहीं करता था। पता चलता था कि उसके बच्चे की परीक्षा है और मकान मालिक उससे घर खाली करने को कह देता। इस पर वह झल्ला कर कहता, घर नहीं खाली करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामान्य शिकायत आती थी। आज ये सारी शिकायतें समाप्त हो गई हैं क्योंकि सरकार ने हर पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले थाना का भवन बनता था लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे। वहां अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थीं। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी। पुलिस कई बार असहाय दिखती थी। अपराधी भाग जाता था। उन्होंने कहा कि पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि थाने में ही उसे रोके रखने की सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय, हर थाना में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे। जो थाने की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन, एडीजी सुरक्षा तरुण गाबा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

घबराइए मत, बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे कोई बाधाः मुख्यमंत्री

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद का अनुरोध किया। साथ में आए बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला की तरफ से नहीं बना है, जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा- घबराइए मत, बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे। महिला का प्रार्थना पत्र लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को इस निर्देश के साथ थमाया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। साथ ही डीएम के जरिये इलाज का इस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। इत्मीनान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए। पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत। सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी।

कूचबिहार रैली में मुख्यमंत्री ममता बोलीं - भाजपा कर रही अत्याचार

हमला बोला

□ भाजपा के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं हैं, वह फॉर्म भरवाकर लोगों को बैठाने की कोशिश कर रही है।

टीम एक्शन इंडिया

कूचबिहार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का प्रचार अभियान अपने चरम पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार जिले के माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र के घोजाडांगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यह सभा तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार साबलू बर्मन के समर्थन में आयोजित की गई थी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न विपक्षी नेता, जिनमें उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव शामिल हैं, उनसे संपर्क में हैं और सभी का मानना है कि बंगाल में भाजपा अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं हैं और वह एजेंसियों के जरिए फॉर्म भरवाकर लोगों को बैठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में पैसे के दम पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसे परिसीमन के साथ जोड़ना एक साजिश है।

'...ताकि नारी शक्ति का वंदन हर घर, हर गली में गूंजे'

टीम एक्शन इंडिया

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से नारी शक्ति वंदन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुरुवार को एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने भारी संख्या में भाग लिया, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प को दर्शाता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने नारी शक्ति वंदन पर अपना बयान देते हुए कहा, "नारी शक्ति वंदन न केवल एक अभियान है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि नारी शक्ति का वंदन हर घर, हर गली में गूंजे।"

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में, धड़ाधड़ कर रहे बैठकें

दिशा-निर्देश

□ मौजूदा व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग हैं

पटना। मुख्यमंत्री बनने के सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं । गुरुवार सुबह सम्राट सचिवालय पहुंच और सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक की। बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ जदयू के विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने भी शपथ ली थी। मौजूदा व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग हैं, जबकि विजय चौधरी को 10 और बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद इन विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा। तब तक तीनों नेता ही सभी विभागों का कार्यभार संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई भवन स्थित जल संसाधन विभाग में पदभार ग्रहण किया एवं विभागीय कार्यों का जायजा लिया। विभागीय प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।

समाजवादी पार्टी पर जिन्ना की सोच हावी हो चुकी : आनन्द दुबे

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए देश में अलग से सीटें आरक्षित करने की मांग करने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनन्द दुबे ने गुरूवार को कहा कि समाजवादी पार्टी पर जिन्ना की सोच हावी हो चुकी है। उन्होंने कहा सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण इस तरह हावी हो गया कि हर जगह उन्हें सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देता है। जिस तरह से जिन्ना मुसलमानों के लिए देश में अलग से आरक्षित चुनाव क्षेत्र की मांग करते थे, आज उसी तरह महिला आरक्षण पर बात करते हुए संसद में सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए देश में अलग से सीटें आरक्षित करने की मांग की। यह वही जिन्ना वाली सोच है जिसने देश का बंटवारा कराया। संविधान और बाबा साहेब का नाम लेने वाली समाजवादी पार्टी की असलियत यही है। विदित हो कि गुरूवार को सपा के सदस्यों ने संसद में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग की।

देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना : मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रगणक घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जनगणना

□ साय ने मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया

आमजन को भयमुक्त वातावरण देना सरकार की प्राथमिकताः मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के साथ हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। शर्मा ने अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रदेश में सुदृढ़ पुलिसिंग से समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे बड़ी संख्या में निवेशक और पर्यटक प्रदेश में आने के उत्सुक हैं और राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

सुरक्षा

□ राजस्थान पुलिस हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे : सीएम

गाजियाबाद की झुग्गी बस्ती में भीषण आग से 150 झुग्गियां जलीं, छह बच्चे लापता होने की आशंका

टीम एक्शन इंडिया

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव की झुग्गी बस्ती में गुरुवार दोपहर को अचानक भीषण आग लगने से 150 से अधिक झुग्गियां जल गईं। आग लगने के दौरान छह बच्चों के लापता होने की खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं बताया गय है। दमकल विभाग की कई टीमें आग पर काबू करने में जुटी हैं। बताया गया कि आज दोपहर को कनवानी गांव में स्थित झुग्गियों में अचानक आग लग गई। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से देखी जा रही थीं। आग लगने की वजह से झुग्गियों में रखे रसोई गैस सिलिंडरों के एक-एक करके फटने के धमाकों की आवाज से पूरा क्षेत्र दहल उठा और लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की अफरा तफरी के बीच छह बच्चों के लापता होने की बात सामने आ रही है। हालांकि कि जिला प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल और दमकल विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया।